गैर-गोपनीय

केस नंबर एडी (एए) – 01/2026

भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
व्यापार उपाय महानिदेशालय

अंतिम निष्कर्ष

चीन पीआर से उत्पन्न या निर्यात किए गए 'ग्लूफोसिनेट और इसके लवण' के आयात पर लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क की अवशोषण जांच

भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-1, खंड-1 में प्रकाशित किया जाएगा।

भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर)

गैर-गोपनीय

चौथी मंजिल, जीवन तारा भवन, **5,** संसद मार्ग,
नई दिल्ली – **110001**
फा. सं. **7/02/2026-** डीजीटीआर

दिनांक**: 01-09-2026**

अंतिम निष्कर्ष
केस नंबर एडी (एए) – **01/2026**

विषय**:** चीन पीआर से उत्पन्न या निर्यात किए गए 'ग्लूफोसिनेट और इसके लवण' के आयात पर लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क की अवशोषण जांच।

सीमा शुल्क टैरिफ (डंप किए गए लेखों की पहचान, मूल्यांकन और एंटी-डंपिंग शुल्क का संग्रहण और चोट के निर्धारण के लिए) नियम, 1995, संशोधित के अनुसार, नामित प्राधिकारी द्वारा मुझे चीन पीआर से उत्पन्न या निर्यात किए गए 'ग्लूफोसिनेट और इसके लवण' के आयात से संबंधित एंटी-अवशोषण जांच के मामले में विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का खुलासा करने का निर्देश दिया गया है।

जांच की पृष्ठभूमि

1. एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 30 के प्रावधानों के अनुसार, सुपरफॉर्म केमिस्ट्रीज लिमिटेड, यूपीएल लिमिटेड, एस्ट्रल लाइफ इंडिया लिमिटेड, यूनाइटेड फॉस्फोरस (इंडिया) एलएलपी, यूपीएल सस्टेनेबल एग्री सॉल्यूशंस लिमिटेड और एसडब्ल्यूएएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने नामित प्राधिकारी (इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें चीन पीआर (इसके बाद "विषय देश" कहा गया है) से उत्पन्न या निर्यात किए गए 'ग्लूफोसिनेट और इसके लवण' (इसके बाद "विषय वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" कहा गया है) के आयात पर लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क के अवशोषण का आरोप लगाया गया।

2. चीन जनवादी गणराज्य से ग्लूफोसिनेट और इसके लवण के आयात से संबंधित एंटी-डंपिंग जांच अधिसूचना सं. 6/19/2024-डीजीटीआर दिनांक 29 जून 2024 द्वारा आरंभ की गई थी। अंतिम निष्कर्ष एफ. सं. 6/19/2024-डीजीटीआर दिनांक 10 फरवरी 2025 के माध्यम से, प्राधिकारी ने 5 वर्षों की अवधि के लिए चीन जनवादी गणराज्य से ग्लूफोसिनेट और इसके लवण के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की। ऐसे शुल्क वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. 09/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 8 मई 2025 के माध्यम से लगाए गए थे। नीचे दी गई तालिका वर्तमान में लागू शुल्क को दर्शाती है:

गैर-गोपनीय

क्रम संख्या	एचएस कोड	उत्पादक	राशि
1	38089193, 38089199, 38089391, 38089399, 38089912, 38089991 और 38089999	कोई भी उत्पादक	2,998 अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन

3. अधिनियम की धारा 9ए(1बी) और नियमों के नियम 29(2) के अनुसार, जहां एंटी-डंपिंग शुल्क के अधीन कोई लेख ऐसी कीमत पर या ऐसी शर्तों के तहत भारत में आयात किया जाता है, जिसे मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क का अवशोषण माना जाता है, जिससे वह शुल्क अप्रभावी हो जाता है या हो सकता है, वहाँ नामित प्राधिकारी, समीक्षा करने के बाद, डंपिंग मार्जिन और चोट मार्जिन का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद शुल्क के रूप या आधार और/या एंटी-डंपिंग शुल्क की मात्रा में संशोधन की सिफारिश कर सकता है। इसी के अनुसार, प्राधिकारी को, घरेलू उद्योग या किसी अन्य हितधारक द्वारा या उनकी ओर से पर्याप्त साक्ष्य के साथ दायर आवेदन के आधार पर, यह समीक्षा करने की आवश्यकता है कि क्या मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क शुल्क के अवशोषण के कारण अप्रभावी हो गया है या हो सकता है।

4. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 7/02/2026-डीजीटीआर दिनांक 2 मार्च 2026 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुई, जिसमें अधिनियम की धारा 9ए और नियमों के नियम 30 के अनुसार, चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के निर्यात पर एंटी-डंपिंग शुल्क के अवशोषण के अस्तित्व और प्रभाव का निर्धारण करने तथा एंटी-डंपिंग शुल्क की मात्रा या रूप में संशोधन की सिफारिश करने के लिए विषय जांच आरंभ की गई।

क. प्रक्रिया

5. जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

1. आरंभ

i. प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 7/02/2026-डीजीटीआर दिनांक 2 मार्च 2026 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की, जिसमें विषय देश से विषय वस्तु के आयात के विरुद्ध अवशोषण जांच आरंभ की गई।

ii. नियम 30(4) के अनुसार, जांच आरंभ होने से पहले, विषय देश की सरकार को उनके भारत स्थित दूतावास के माध्यम से वर्तमान अवशोषण आवेदन की प्राप्ति के बारे में सूचित किया गया था।

iii. नियम 6(2) के अनुसार, हितधारकों को आरंभ अधिसूचना की एक प्रति विषय देश के भारत स्थित दूतावास, विषय देश में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में विषय वस्तु के ज्ञात आयातकों और अन्य हितधारकों को, आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, साझा करके जांच आरंभ होने की सूचना दी गई थी।

2. जांच अवधि (पीओआई)

i. जैसा कि आरंभ अधिसूचना में उल्लेख किया गया है, अवशोषण अवधि जनवरी 2025 से सितंबर 2025 (9 माह) मानी गई थी। प्राधिकारी ने ऐसी अवधि में कीमतों की तुलना मूल जांच की जांच अवधि, अर्थात 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 ("मूल पीओआई") से की है।

3. आयात डेटा

i. अवशोषण अवधि के लिए विषय वस्तु का लेन-देन-वार आयात डेटा प्राप्त करने के लिए डीजी सिस्टम्स से अनुरोध किया गया था। डेटा प्राप्त किया गया था और उचित परीक्षण के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए उस पर भरोसा किया गया है। आयात की मात्रा और मूल्य को डीजी सिस्टम्स के लेन-देन-वार आंकड़ों के आधार पर माना गया है।

4. आवेदन की गैर-गोपनीय प्रति का वितरण

i. नियम 6(3) के अनुसार, आवेदन की गैर-गोपनीय प्रति की एक प्रति विषय देश की सरकार को उनके भारत स्थित दूतावास के माध्यम से, विषय देश से विषय वस्तु के ज्ञात निर्यातकों को, भारत में ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं को और अन्य हितधारकों को, जिन्होंने आवेदन की एक प्रति के लिए लिखित में अनुरोध किया था, प्रदान की गई थी।

5. विषय देश के निर्यातकों द्वारा भागीदारी

i. नियम 6(4) के अनुसार, सामान्य मूल्य और शुद्ध निर्यात मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी गई थी: लियर केमिकल कंपनी लिमिटेड; एग्रोड्रैगन कंपनी लिमिटेड; बीएएसएफ; शेडोंग बिनोंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड; लिमेन केमिकल कंपनी लिमिटेड; फुहुआ टोंगडा एग्रो-केमिकल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड; योंगनोंग बायोसाइंसेज कंपनी लिमिटेड; जियांगसू हुइफेंग बायो

एग्रीकल्चर कंपनी लिमिटेड; शंघाई किझोउ ज़ियुई कंपनी लिमिटेड; और वेइफांग ज़िनलु केमिकल कंपनी लिमिटेड।

ii. निर्यातक प्रश्नावली विषय देश की सरकार को भी उनके भारत स्थित दूतावास के माध्यम से भेजी गई थी, जिसमें अनुरोध किया गया था कि वे इसे विषय वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों को अग्रेषित करें और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब देने की सलाह दें।

iii. जवाब में, विषय देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का जवाब दायर किया: (1) जियांगशुई झोंगशान बायोसाइंस कंपनी लिमिटेड; और (2) झेजियांग झोंगशान केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड। दोनों कंपनियाँ संबद्ध हैं, पूर्व उत्पादक है और बाद वाली निर्यातक है, और उन्हें एक साथ "भाग लेने वाले निर्यातक" के रूप में संदर्भित किया गया है।

6. आयातकों/उपयोगकर्ताओं और उनके संघों द्वारा भागीदारी

i. नियम 6(4) के अनुसार, भारत में विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं को भी प्रश्नावली भेजी गई थी: क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड; कृषि रसायन; बीएएसएफ इंडिया; और अमिश क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड।

ii. जवाब में, निम्नलिखित आयातकों/उपयोगकर्ताओं ने आयातक/उपयोगकर्ता प्रश्नावली का जवाब दायर किया: (1) झोंगशान क्रॉप साइंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड; और (2) टेफ्रा बायोसाइंस एलएलपी।

7. पंजीकृत हितधारक

i. निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वयं को पंजीकृत करने वाले सभी हितधारकों की एक सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। सभी पंजीकृत हितधारकों को अपनी सभी प्रस्तुतियों की गैर-गोपनीय प्रति अन्य सभी हितधारकों को वितरित करने का निर्देश दिया गया था।

8. मौखिक सुनवाई

i. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 20 मई 2026 को आयोजित एक सुनवाई में हितधारकों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षों को मौखिक रूप से व्यक्त किए

गए विचारों के लिखित प्रस्तुतीकरण दाखिल करने का निर्देश दिया गया, उसके बाद यदि कोई हो तो जवाबी प्रस्तुतियाँ दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

9. आगे की प्रक्रिया

i. विदेशी उत्पादकों, निर्यातकों और अन्य हितधारकों, जिन्होंने जवाब नहीं दिया है, या इस जांच से प्रासंगिक जानकारी प्रदान नहीं की है, को गैर-सहयोगी माना गया है।

ii. नियम 6(8) के अनुसार, जहां किसी हितधारक ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान आवश्यक जानकारी तक पहुंचने से इनकार कर दिया है, या अन्यथा समय पर आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डाली है, ऐसे पक्षों को गैर-सहयोगी माना गया है, और निष्कर्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दर्ज किए गए हैं।

iii. नियम 7 के अनुसार, हितधारकों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की ऐसी गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, जहां आवश्यक समझा गया, वहाँ गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया गया, और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया और अन्य हितधारकों को प्रकट नहीं किया गया। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षों को उसकी पर्याप्त गैर-गोपनीय प्रति प्रदान करने का निर्देश दिया गया।

iv. गैर-हानिकारक मूल्य भारत में घरेलू समान लेख की इष्टतम उत्पादन लागत और बिक्री लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसमें आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमों के अनुलग्नक III में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया है, जैसा कि नियम 29(2) के अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया गया है।

v. सभी हितधारकों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और प्रदान की गई सभी जानकारियों पर, जहां तक वे साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक पाए गए हैं, विचार किया गया है।

vi. जांच के ज़रूरी तथ्यों वाला एक डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट (जिसके आधार पर अंतिम निष्कर्ष निकाला गया) 20 अगस्त 2026 को संबंधित पक्षों को जारी किया गया था और उन्हें इस पर अपनी राय देने के लिए 26 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया था। इस अंतिम निष्कर्ष की सूचना में संबंधित पक्षों द्वारा दी गई जानकारी, उनकी दलीलों और डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट पर उनकी

टिप्पणियों पर विचार किया गया है–बशर्ते वे प्रासंगिक हों, दोहराव वाली न हों और सबूतों के साथ हों।

vii. इस प्रकटीकरण विवरण में '***' उस सूचना को दर्शाता है जो किसी हितधारक द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई है और नियमों के तहत ऐसी ही मानी गई है।

viii. विषय जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 87.26 रुपये है। मूल जांच में मानी गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 83.52 रुपये थी।

ख. विभिन्न मुद्दों पर अन्य हितधारकों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

6. जांच के दौरान अन्य हितधारकों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

i. उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि हालांकि उन्होंने 8 अप्रैल 2026 को हितधारक के रूप में पंजीकरण कराया था, लेकिन उनका पंजीकरण केवल 15 अप्रैल 2026 को पुष्ट किया गया था। तदनुसार, आवेदन की गैर-गोपनीय प्रति प्रभावी रूप से केवल 15 अप्रैल 2026 को उपलब्ध कराई गई थी। नतीजतन, प्रश्नावली का जवाब दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 मई 2026 के बजाय 22 मई 2026 होनी चाहिए थी, और 7 जून 2026 तक समय विस्तार, विलंब के माफी के साथ, मांगा गया था।

ii. वर्तमान अवशोषण जांच का आरंभ अस्थिर है क्योंकि आवेदक नियम 29 और 30 के तहत प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में विफल रहे। आवेदन अपूर्ण और अपर्याप्त साक्ष्य पर आधारित है और मुख्य रूप से निर्यात कीमतों में कथित गिरावट पर निर्भर करता है, बिना अन्य प्रासंगिक कारकों की जांच किए, जिनमें चीन में उत्पादन लागत में परिवर्तन, भारत में पुनर्विक्रय मूल्य, बाजार की स्थितियाँ और तीसरे देशों को निर्यात मूल्य शामिल हैं।

iii. निर्यात कीमतों में मात्र गिरावट अवशोषण स्थापित नहीं करती है। नियम 29 के लिए यह जांच आवश्यक है कि क्या गिरावट एंटी-डंपिंग शुल्क के अवशोषण के कारण है, न कि उत्पादन लागत में कमी जैसे अन्य कारकों के कारण। वर्तमान मामले में, चीन में उत्पादन लागत में कोई प्रदर्शित कमी नहीं हुई है, न ही आवेदकों ने भारत में पुनर्विक्रय मूल्य या चीन में उत्पादन लागत से संबंधित डेटा प्रस्तुत किया है। नियम 29 के विपरीत घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत पर निर्भरता है।

iv. आवेदक आवेदन में भरोसा किए गए निर्यात मूल्य डेटा, आयात मात्रा डेटा और लागत सूचना के स्रोत और आधार का खुलासा करने में विफल रहे हैं। निर्यात

मूल्य डेटा संपूर्ण अवशोषण अवधि को कवर नहीं करता है और उत्पादन लागत में कथित परिवर्तन साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं।

v. आवेदकों द्वारा भरोसा किए गए तीसरे देशों को निर्यात मूल्य के साक्ष्य में केवल दो चीनी निर्यातकों से संबंधित चयनित चालान शामिल हैं और ये वास्तविक निर्यात, डिलीवरी या भुगतान के साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं। ऐसे चालान संबंधित निर्यातकों द्वारा प्रमाणित नहीं किए गए हैं और इसलिए अवशोषण जांच का आधार नहीं बन सकते हैं।

vi. भारत को निर्यात कीमतों में कथित गिरावल तीसरे देशों को निर्यात कीमतों में गिरावट के अनुरूप है और इसलिए यह अवशोषण स्थापित नहीं करती है। इसके अलावा, एक बार लागू एंटी-डंपिंग शुल्क और न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) पर विचार करने पर, मूल जांच अवधि की तुलना में भारत को निर्यात कीमतों में वास्तव में वृद्धि हुई है।

vii. घरेलू उद्योग ने पूरी अवशोषण अवधि के दौरान एमआईपी संरक्षण का आनंद लेना जारी रखा है, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया है। अवशोषण अवधि के दौरान कथित 71 मीट्रिक टन आयात में से, लगभग 56 मीट्रिक टन (लगभग 80%) 15 अमेरिकी डॉलर/किग्रा से अधिक कीमतों पर आयात किए गए थे, जो दर्शाता है कि अधिकांश आयात को अवशोषित आयात नहीं माना जा सकता है।

viii. नियम 29 केवल एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने के बाद लागू होता है। इसलिए, प्राधिकारी के पास 8 मई 2025 से पहले किए गए आयात की जांच करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। प्रस्तावित नौ-माही पीओआई में शुल्क-पूर्व अवधि को अनुचित रूप से शामिल किया गया है, जिससे शुल्क-पश्चात् केवल चार महीने का डेटा बचता है, जो किसी सार्थक अवशोषण विश्लेषण के लिए अपर्याप्त है।

ix. हालांकि नियम 29 एक विशिष्ट पीओआई निर्धारित नहीं करता है, लेकिन प्राधिकारी का विवेक असीमित नहीं है। पीओआई का निर्धारण नियम 5(3ए)(ii) द्वारा निर्देशित होना चाहिए, जो एक सामान्य बारह-माही पीओआई की परिकल्पना करता है और किसी भी विचलन के लिए दर्ज किए गए कारणों की आवश्यकता होती है, जैसा कि कल्याणी स्टील्स लिमिटेड बनाम भारत संघ में मान्यता प्राप्त है।

x. आवेदकों ने स्वयं नौ-माही पीओआई का प्रस्ताव रखा था, जिसे प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। हालाँकि, नियम 29 के तहत वर्तमान जांच अवधि की तुलना मूल जांच अवधि से करने का कोई कानूनी आधार नहीं है, और कराधान क़ानूनों की सख्त व्याख्या की जानी चाहिए, बिना नियम में ऐसी आवश्यकताओं को पढ़े जो मौजूद नहीं हैं।

xi. आवेदक यह स्थापित करने में विफल रहे हैं कि मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क अप्रभावी हो गया है। आवेदकों के अपने डेटा के अनुसार, एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने के

बाद भारत में केवल लगभग 56 मीट्रिक टन आयात हुआ, जिसमें से केवल लगभग 10 मीट्रिक टन कथित तौर पर कम कीमतों पर आयात किए गए थे। ऐसी नगण्य मात्राएँ नियम 29 के तहत शुल्क अवशोषण स्थापित नहीं कर सकती हैं।

xii. एंटी-डंपिंग शुल्क के रूप में संशोधन का अनुरोध नियम 29(2) द्वारा समर्थित नहीं है। आवेदकों ने न तो यह उचित ठहराया है कि संशोधन क्यों आवश्यक है और न ही शुल्क के संशोधित रूप को निर्दिष्ट किया है। कोई भी संशोधन प्राधिकारी के स्वतंत्र उद्देश्यपूर्ण विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए और एमआईपी की समाप्ति के बारे में आवेदकों की आशंका पर आधारित नहीं हो सकता है, क्योंकि एमआईपी और एंटी-डंपिंग शुल्क अलग-अलग और परस्पर अनन्य व्यापार उपचारात्मक उपाय हैं।

xiii. एक अवशोषण समीक्षा का दायरा मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क की प्रभावशीलता को बहाल करने तक सीमित है। यह शुल्क के रूप या संरचना पर पुनर्विचार की अनुमति नहीं देता है, जो केवल एक उचित मध्य-अवधि या सूर्यास्त समीक्षा में ही किया जा सकता है।

xiv. आवेदक एंटी-डंपिंग शुल्क के पूर्वव्यापी संशोधन को उचित ठहराने में विफल रहे हैं।

xv. अधिसूचित एमआईपी से नीचे कोई भी आयात सीमा शुल्क या डीजीएफटी प्रवर्तन में कमियों को इंगित करता है, न कि एंटी-डंपिंग शुल्क के अवशोषण को। एमआईपी का प्रवर्तन सीमा शुल्क अधिकारियों और डीजीएफटी के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसे अवशोषण कार्यवाही के माध्यम से संबोधित नहीं किया जा सकता है।

xvi. आवेदकों ने नियम 7 का उल्लंघन किया है, भारत और तीसरे देशों को निर्यात कीमतों, खरीद विवरण, भूमि मूल्य गणना, शुद्ध निर्यात मूल्य, सामान्य मूल्य, डंपिंग मार्जिन, चोट मार्जिन और मूल जांच में निर्धारित गैर-हानिकारक मूल्य पर अत्यधिक गोपनीयता का दावा करके, जिससे हितधारकों को सार्थक बचाव करने से रोका गया।

xvii. यूपीएल घरेलू उद्योग का गठन करने के लिए पात्र नहीं है। आवेदकों ने आवेदकों के साथ अपने संबंध का खुलासा किए बिना हांगकांग और यूएई में स्थित यूपीएल संस्थाओं से जुड़े चालानों पर भरोसा किया। आवेदक स्वयं विषय वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हो सकते हैं।

xviii. आयातकों से अंतरिम मूल्यांकन और गारंटी का अनुरोध अनुचित है, क्योंकि यह वैध व्यापार को बाधित करेगा, अनुपालन बोझ बढ़ाएगा और आवेदन स्वयं अपर्याप्त साक्ष्य पर आधारित होने के बावजूद बाजार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

xix. अवशोषण कार्यवाही निर्यातक-विशिष्ट होती है और प्रत्येक निर्यातक के आचरण का उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन आवश्यक है। जिन निर्यातकों ने एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए

जाने के बाद अपनी निर्यात कीमतों में कमी नहीं की है, या जिन्होंने प्रासंगिक अवधि के दौरान निर्यात नहीं किया है, उन्हें केवल इस आधार पर बढ़े हुए अवशोषण शुल्कों के अधीन नहीं किया जा सकता है कि अन्य निर्यातकों ने कथित तौर पर शुल्क को अवशोषित कर लिया है।

xx. एंटी-डंपिंग शुल्कों में कोई भी वृद्धि या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर डाउनस्ट्रीम उद्योगों और उपयोगकर्ताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, जिससे इनपुट लागत बढ़ेगी, घरेलू और निर्यात बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता कम होगी, और अंततः अंतिम उपभोक्ताओं, विशेष रूप से किसानों के लिए लागत बढ़ेगी।

ग. विभिन्न मुद्दों पर घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

7. जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद ग्लूफोसिनेट और इसके लवण हैं, तकनीकी और फॉर्मूलेशन दोनों रूपों में। हालांकि सीमा शुल्क टैरिफ वर्गीकरण और एचएस कोड समय के साथ बदल गए हैं, विचाराधीन उत्पाद का दायरा अपरिवर्तित रहा है।

ii. विचाराधीन उत्पाद के आयात एंटी-डंपिंग शुल्क और एमआईपी दोनों उपायों के अधीन रहे हैं। लगातार एमआईपी अधिसूचनाएँ, जिनका समापन 13 अप्रैल 2026 की अधिसूचना में हुआ, एमआईपी के दायरे को एंटी-डंपिंग शुल्क के साथ संरेखित करती हैं और स्पष्ट रूप से एंटी-डंपिंग शुल्क को कारक बनाती हैं, जो दर्शाता है कि अकेले मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क हानिकारक कीमतों पर आयात को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं रहा है।

iii. हितधारक निर्धारित समय सीमा के भीतर गोपनीयता टिप्पणियाँ और प्रश्नावली का जवाब दाखिल करके प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रहे। विस्तार के अनुरोध घरेलू उद्योग द्वारा चूक बताए जाने के बाद देरी से किए गए थे और इसलिए प्रक्रियात्मक गैर-अनुपालन को ठीक नहीं कर सकते हैं।

iv. जांच पूरी करने के लिए प्राधिकारी की आंतरिक समय-सीमा हितधारकों को निर्धारित समय-सीमा से परे विस्तार मांगने का कोई अधिकार नहीं देती है।

v. आर्थिक हित प्रश्नावली अवशोषण जांच में अप्रासंगिक है। नियम 29 के तहत कार्यवाही इस बात की जांच करने तक सीमित है कि क्या निर्यातकों ने एंटी-डंपिंग शुल्क को अवशोषित किया है और मूल जांच में पहले से निर्धारित डंपिंग, चोट,

कारणात्मक संबंध, घरेलू उद्योग या सार्वजनिक हित से संबंधित मुद्दों को फिर से नहीं खोलती है।

vi. एंटी-डंपिंग शुल्क की निरंतरता और प्रभावी प्रवर्तन सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं है। घरेलू उद्योग के पास घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है, उसने महत्वपूर्ण निवेश किए हैं, रोजगार सृजित किया है और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान दिया है। इसके अलावा, एंटी-डंपिंग शुल्क से फॉर्मूलेशन की एक बोतल की लागत में केवल लगभग 35-36 रुपये की वृद्धि होगी, जो एक एकड़ खेती के लिए पर्याप्त है, जिसका किसानों पर नगण्य प्रभाव पड़ता है।

vii. नियम 29 के लिए प्राधिकारी को यह जांचना आवश्यक है कि क्या निर्यातकों ने उत्पादन लागत में संगत कमी के बिना निर्यात कीमतों में कमी की है, जिससे मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क अप्रभावी हो गया है। नियम 29(2) केवल पहले से निर्धारित सामान्य मूल्य और चोट मापदंडों के समायोजन की अनुमति देता है और सामान्य मूल्य, चोट या चीन की गैर-बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति के ताजा निर्धारण की आवश्यकता नहीं होती है।

viii. मूल जांच में निर्धारित निर्यात मूल्य *** अमेरिकी डॉलर/किग्रा था, जबकि अवशोषण अवधि के दौरान औसत एफओबी निर्यात मूल्य घटकर *** अमेरिकी डॉलर/किग्रा हो गया, जो एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने के बावजूद लगभग 44% की गिरावट दर्शाता है।

ix. आवेदकों ने चीन सीमा शुल्क निर्यात डेटा से प्राप्त वास्तविक निर्यात कीमतों पर भरोसा किया। चूंकि भारत में आयात एमआईपी के अधीन थे, भारतीय सीमा शुल्क आयात मूल्य एमआईपी अनुपालन द्वारा कृत्रिम रूप से प्रभावित थे और इसलिए निर्यातकों के वास्तविक मूल्य निर्धारण व्यवहार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। लेन-देन-वार निर्यात डेटा लगातार लगभग 5.78-5.79 अमेरिकी डॉलर/किग्रा की कीमतों को दर्शाता है।

x. निर्यात कीमतों में गिरावट उत्पादन लागत में किसी भी अनुरूप कमी से स्पष्ट नहीं होती है। जबकि कच्चे माल की लागत में केवल लगभग 100 रुपये/किग्रा की कमी आई, निर्यात कीमतों में लगभग 335 रुपये/किग्रा की कमी आई। भाग लेने वाले निर्यातकों ने न तो बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा किया और न ही उत्पादन लागत में कोई संगत कमी स्थापित की।

xi. यह तर्क कि नियम 29 संतुष्ट नहीं है क्योंकि तीसरे देशों को निर्यात कीमतों में भी कमी आई है, गलत है। धारा 9ए(1बी) और नियम 29 'या' शब्द का उपयोग करते हैं, जिससे प्रत्येक शर्त स्वतंत्र हो जाती है। एक बार निर्यात कीमतों में बिना उत्पादन लागत में संगत कमी के कमी आने पर, अवशोषण स्थापित हो जाता है।

xii. आवेदकों ने सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी पर भरोसा किया, जिसमें चीन सीमा शुल्क डेटा, लेन-देन-वार निर्यात कीमतें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित कच्चे माल की कीमतें, तीसरे देशों को निर्यात डेटा और खरीद चालान शामिल हैं। घरेलू उत्पादकों से निर्यातकों के आंतरिक लागत रिकॉर्ड या भारत में पुनर्विक्रय मूल्य रखने की उचित रूप से अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

xiii. आवेदकों ने केवल कच्चे माल की लागत पर भरोसा नहीं किया है। उनका दावा निर्यात कीमतों, आयात मात्राओं, उत्पादन लागत और संपूर्ण अवशोषण अवधि को कवर करने वाले अन्य पुष्टिकारी साक्ष्यों पर आधारित है।

xiv. भाग लेने वाले निर्यातकों ने स्वयं निर्यात कीमतों में गिरावट के अनुरूप अपनी उत्पादन लागत में किसी भी कमी को प्रदर्शित करने वाला साक्ष्य नहीं रखा। नतीजतन, उनके खिलाफ प्रतिकूल अनुमान लगाया जा सकता है।

xv. नियम 29(2) प्राधिकारी को एंटी-डंपिंग शुल्क के रूप, आधार और मात्रा को संशोधित करने के लिए स्पष्ट रूप से सशक्त बनाता है। चूंकि डंपिंग और चोट दोनों मार्जिन बढ़ गए हैं और भूमि मूल्य समायोजित गैर-हानिकारक मूल्य से नीचे बना हुआ है, मौजूदा उपाय में संशोधन उचित है।

xvi. संशोधन का अनुरोध पूरी तरह से शुल्क अवशोषण के साक्ष्य पर आधारित है, न कि एमआईपी के अस्तित्व या समाप्ति पर। एमआईपी की बाद की निरंतरता, जबकि स्पष्ट रूप से एंटी-डंपिंग शुल्क को कारक बनाती है, यह भी दर्शाती है कि मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क अपने इच्छित उपचारात्मक प्रभाव को प्राप्त नहीं कर पाया है।

xvii. मूल जांच के दौरान घरेलू उद्योग ने स्वयं एमआईपी के अस्तित्व के कारण बेंचमार्क-रूप शुल्कों का अनुरोध किया था। बाद के नियामक विकास शुल्क के रूप और मात्रा दोनों में संशोधन की आवश्यकता को पुष्ट करते हैं।

xviii. गोपनीयता के संबंध में आपत्तियाँ देरी से उठाई गई हैं। किसी भी स्थिति में, गोपनीय उपचार केवल व्यावसायिक-संवेदनशील जानकारी के लिए दावा किया गया है। सार्थक गैर-गोपनीय सारांश और अनुक्रमित गणना व्यापार सूचना सं. 10/2018 के अनुसार प्रदान की गई थी, और हितधारक उन्हें हुई किसी भी वास्तविक हानि की पहचान करने में विफल रहे हैं।

xix. यूपीएल घरेलू उत्पादक के रूप में पात्र बना हुआ है। हितधारकों द्वारा भरोसा किए गए लेन-देन विदेशी संबद्ध संस्थाओं द्वारा की गई खरीद से संबंधित हैं, न कि यूपीएल द्वारा भारत में आयात से। किसी भी स्थिति में, स्थिति मूल जांच में निर्णायक रूप से निर्धारित की गई थी और इसे फिर से नहीं खोला जा सकता है।

xx. नियम 31 स्पष्ट रूप से एक बार अवशोषण स्थापित हो जाने पर आरंभ की तारीख से किसी भी संशोधित एंटी-डंपिंग शुल्क के पूर्वव्यापी आवेदन का अधिकार देता है।

xxi. नियम 29(3) जांच अवधि निर्धारित नहीं करता है। तदनुसार, प्राधिकारी द्वारा चुनी गई अवशोषण अवधि, जिसमें शुल्क-पश्चात् लेन-देन शामिल हैं, नियमों के अनुरूप है।

xxii. एंटी-एब्जॉर्प्शन अवधि के दौरान लागू निर्यात कीमतों की तुलना मूल जांच में तय की गई कीमतों से करना नियम 29 का एक ज़रूरी हिस्सा है। यह अथॉरिटी की पिछली एंटी-एब्जॉर्प्शन जांचों और यूरोपियन कमीशन द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुरूप भी है।

xxiii. एंटी-एब्जॉर्प्शन जांच में आयात की मात्रा निर्णायक नहीं होती है। आयात की कम मात्रा भी यह दिखा सकती है कि निर्यातकों ने एंटी-डंपिंग ड्यूटी को खुद वहन किया है और भविष्य में नुकसान पहुंचाने वाले आयात की संभावना का संकेत दे सकती है।

xxiv. उत्पादन लागत में कोई कमी किए बिना निर्यात कीमतों में भारी गिरावट को देखते हुए, मौजूदा एंटी-डंपिंग ड्यूटी को चीनी निर्यातकों ने खुद वहन कर लिया है और अब इससे वह सुधारात्मक असर नहीं मिल रहा है जिसके लिए इसे लागू किया गया था। इसलिए, अथॉरिटी को नियम 29(2) के तहत एंटी-डंपिंग ड्यूटी के स्वरूप, आधार और मात्रा में बदलाव करना चाहिए।

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच

8. चूंकि वर्तमान जांच लागू एंटी-डंपिंग शुल्क की अवशोषण समीक्षा है, विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच में परिभाषित के अनुरूप ही रहेगा। मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा अंतिम निष्कर्ष एफ. सं. 6/19/2024-डीजीटीआर दिनांक 10 फरवरी 2025 के माध्यम से निर्धारित विचाराधीन उत्पाद का दायरा, जो एंटी-डंपिंग शुल्क के अंतर्गत आता है, निम्नलिखित है:

> *"18. उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा ग्लूफोसिनेट और इसके लवण हैं, तकनीकी और फॉर्मूलेशन दोनों रूपों में।"*

9. ग्लूफोसिनेट एक शाकनाशी है जो खरपतवारों की व्यापक स्पेक्ट्रम को नियंत्रित करने में अपनी प्रभावशीलता के लिए जाना जाता है। इसका सक्रिय घटक पौधे की कुछ आवश्यक अमीनो एसिड का उत्पादन करने की क्षमता को बाधित करता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण का निषेध और उसके बाद पौधे की मृत्यु हो जाती है। यह

ऑर्गेनोफॉस्फोरस रासायनिक परिवार से संबंधित एक फॉस्फिनिक एसिड है, जो शाकनाशियों के किसी अन्य रासायनिक वर्ग से अलग है।

10. विचाराधीन उत्पाद का कोई समर्पित वर्गीकरण नहीं है। वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, कोड 38089193, 38089199, 38089391, 38089399, 38089912, 38089991 और 38089999 पर विचार किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण कोड केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

11. प्राधिकारी ने नोट किया कि वर्तमान जांच एक अवशोषण जांच है, और इसका उद्देश्य यह जांचना है कि क्या निर्यात मूल्य उत्पादन लागत के अनुरूप रहा है। किसी भी हितधारक ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर कोई प्रस्तुति नहीं दी है, न ही किसी हितधारक ने दावा किया है कि मूल जांच में निर्यात किए गए उत्पाद और वर्तमान जांच में निर्यात किए गए उत्पाद में कोई अंतर है। तदनुसार, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विषय वस्तु को चीन जनवादी गणराज्य से आयातित उत्पाद के 'समान लेख' के रूप में माना जाता है, और प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद या समान-लेख के दायरे के मुद्दे की आगे जांच करना आवश्यक नहीं समझता है।

विविध मुद्दे, समयबद्धता, स्थिति और गोपनीयता

12. विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की गैर-गोपनीय प्रति नियम 6(7) और व्यापार सूचना सं. 10/2018 दिनांक 7 सितंबर 2018 के अनुसार सभी हितधारकों को उपलब्ध कराई गई थी। नियमों का नियम 7 निम्नलिखित प्रावधान करता है:

> *"(1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7) में किसी भी बात के होते हुए भी ... उप-नियम (1) के तहत प्राप्त आवेदनों की प्रतियाँ, या जांच के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर नामित प्राधिकारी को प्रदान की गई कोई अन्य जानकारी, नामित प्राधिकारी द्वारा उसकी गोपनीयता के बारे में संतुष्ट होने पर, ऐसी ही मानी जाएगी और ऐसी कोई जानकारी ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी अन्य पक्ष को प्रकट नहीं की जाएगी।*
>
> *(2) नामित प्राधिकारी गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षों को उसका गैर-गोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है ... (3) ... यदि नामित प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है ... तो वह ऐसी जानकारी को नजरअंदाज कर सकता है।"*

13. प्राधिकारी ने गोपनीयता पर घरेलू उद्योग और अन्य हितधारकों की प्रस्तुतियों की जांच की है। आरंभ अधिसूचना ने सभी हितधारकों को गोपनीयता के दावों पर गैर-गोपनीय दस्तावेजों के वितरण से सात दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर टिप्पणियाँ देने का अवसर प्रदान किया। अन्य हितधारकों से निर्धारित समय के भीतर

गोपनीयता पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई, और आपत्तियाँ पहली बार मौखिक सुनवाई के बाद दायर लिखित प्रस्तुतियों में उठाई गईं। प्राधिकारी ने नोट किया कि गोपनीयता का दावा सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य, डंपिंग मार्जिन, चोट मार्जिन, मूल्य समायोजन, बिक्री और खरीद दस्तावेज, तथा ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के नाम जैसी सूचनाओं के संबंध में किया गया है, जो सभी व्यावसायिक-संवेदनशील जानकारी का गठन करती हैं। नियम 7 और प्राधिकारी की सुसंगत प्रथा के अनुसार, और व्यापार सूचना सं. 10/2018 को ध्यान में रखते हुए, भारित-औसत सामान्य मूल्य, गैर-हानिकारक मूल्य, डंपिंग मार्जिन और चोट मार्जिन जैसे संवेदनशील मापदंडों को श्रेणियों के रूप में प्रकट किया गया है। प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता के दावे उचित हैं और रिकॉर्ड पर मौजूद गैर-गोपनीय संस्करण हितधारकों को प्रस्तुत जानकारी के सार को उचित रूप से समझने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करते हैं। गोपनीयता के दुरुपयोग का तर्क, तदनुसार, स्वीकार नहीं किया जाता है।

14. हितधारकों ने तर्क दिया कि प्रश्नावली का जवाब बाद की तारीख में देय था और समय विस्तार और विलंब की माफी मांगी। प्राधिकारी ने विस्तार के अनुरोध पर विचार किया और उसे स्वीकार कर लिया। तदनुसार, विस्तार के बाद दायर की गई प्रस्तुतियों पर, जहां तक प्रासंगिक हैं, योग्यता के आधार पर विचार किया गया है। चूंकि भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने न तो बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा किया और न ही बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली दायर की, सत्यापनीय लागत और मूल्य डेटा उपलब्ध नहीं है। तदनुसार, सामान्य मूल्य मूल जांच में अपनाई गई पद्धति के अनुसार निर्धारित किया गया है, जैसा कि खंड E3 में चर्चा की गई है।

15. अन्य हितधारकों ने तर्क दिया है कि आवेदन प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं करता है, कि नियम 30(2) के तहत साक्ष्य अपर्याप्त हैं, और इसलिए आरंभ अस्थिर है। प्राधिकारी ने नोट किया कि नियम 30(2) के लिए आवेदन में नियम 29(1) में संदर्भित परिस्थितियों के अस्तित्व के संबंध में आरंभ को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य होने की आवश्यकता है। आवेदन में विषय वस्तु का लेन-देन-स्तरीय आयात डेटा, मूल जांच की तुलना में निर्यात कीमतों में गिरावट के साक्ष्य, कच्चे माल की कीमतों पर तृतीय-पक्ष डेटा और तीसरे देशों को निर्यात मूल्य, तथा पुनर्मूल्यांकित डंपिंग और चोट मार्जिन शामिल थे। प्राधिकारी ने स्वयं को प्रथम दृष्टया साक्ष्य की पर्याप्तता और यथेष्टता के बारे में संतुष्ट करते हुए, आरंभ अधिसूचना दिनांक 2 मार्च 2026 में अपने कारण दर्ज किए। आरंभ के लिए साक्ष्य की पर्याप्तता का आकलन आरंभ के चरण में उपलब्ध सामग्री के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि अंतिम निर्धारण पर लागू मानक से। प्राधिकारी संतुष्ट है कि साक्ष्य आरंभ को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त थे, और तर्क स्वीकार नहीं किया जाता है।

16. अन्य हितधारकों ने तर्क दिया है कि यूपीएल, निर्यातकों से संबंधित या स्वयं पीयूसी के आयातक होने के कारण, घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने योग्य नहीं है। प्राधिकारी ने नोट किया कि घरेलू उद्योग की स्थिति और नियम 2(बी) के तहत उसकी पात्रता की मूल जांच में जांच और निर्धारण किया गया था। नियम 29 के तहत एक अवशोषण जांच दायरे में सीमित है, यह जांचने के लिए कि क्या निर्यातकों ने लागू एंटी-डंपिंग शुल्क को अवशोषित किया है, और यह स्थिति, समान-लेख, चोट और कारणात्मक संबंध जैसे मुद्दों को फिर से नहीं खोलती है जो मूल जांच में निर्धारित किए गए थे। किसी भी स्थिति में, घरेलू उद्योग ने कहा है कि यूपीएल ने चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है, और हितधारकों द्वारा भरोसा की गई खरीद भारत के बाहर स्थित संबद्ध संस्थाओं द्वारा की गई थी। प्राधिकारी वर्तमान कार्यवाही में घरेलू उद्योग की स्थिति की फिर से जांच करना आवश्यक नहीं समझता है, और तर्क स्वीकार नहीं किया जाता है। प्राधिकारी उत्तरदायी आयातकों में से एक की व्यावसायिक प्रकृति और उसकी गतिविधियों की प्रकृति के बारे में घरेलू उद्योग की प्रस्तुति को भी समान रूप से नोट करता है। वर्तमान कार्यवाही में निर्धारण विषय देश के निर्यातकों के निर्यात मूल्य निर्धारण व्यवहार पर निर्भर करता है, न कि रिकॉर्ड पर आयातकों की व्यावसायिक प्रकृति पर, और प्राधिकारी तदनुसार उस प्रस्तुति की जांच करना आवश्यक नहीं समझता है।

17. अन्य हितधारकों ने तर्क दिया है कि शुल्क के रूप में संशोधन और कोई भी पूर्वव्यापी आवेदन अवशोषण कार्यवाही के दायरे से बाहर होगा, कि मांगी गई राहत दंडात्मक और निर्यातक-अज्ञेय है, और वृद्धि उपयोगकर्ता उद्योग और किसानों के लिए हानिकारक होगी। प्राधिकारी ने नोट किया कि नियम 29(2) स्पष्ट रूप से प्राधिकारी को, अवशोषण स्थापित करने पर, शुल्क के रूप या आधार, या शुल्क की मात्रा, या दोनों में संशोधन की सिफारिश करने के लिए सशक्त बनाता है, और नियम 31 पूर्वव्यापी आवेदन के रूप में सिफारिश की अनुमति देता है। वर्तमान जांच नियम 29(2) के अनुसार डंपिंग और चोट मार्जिन के पुनर्निर्धारण तक सीमित है; किसी भी संशोधन की सीमा, रूप और आवेदन की तारीख अंतिम निष्कर्ष में प्राधिकारी की सिफारिश के मामले हैं, जो कम-शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए किए जाने हैं। जहां तक उपयोगकर्ता हित का संबंध है, सार्वजनिक हित के मुद्दों की मूल जांच में जांच की गई थी, और घरेलू उद्योग ने प्रदर्शित किया है कि शुल्क का अंतिम उपभोक्ता पर प्रति-इकाई प्रभाव नगण्य है। ये तर्क नीचे की जा रही अवशोषण की जांच से अलग नहीं होते हैं।

एंटी-डंपिंग शुल्क का अवशोषण

18. एंटी-डंपिंग नियमों का नियम 29(1) प्रावधान करता है कि एक एंटी-डंपिंग शुल्क तब अवशोषित माना जा सकता है जब निर्यात करने वाले देश से किसी लेख के निर्यात मूल्य एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने के बाद ऐसे लेख की उत्पादन लागत में किसी अनुरूप परिवर्तन के बिना कम हो जाते हैं, या भारत के अलावा अन्य देशों को ऐसे लेख के निर्यात मूल्य कम हो जाते हैं, या भारत में ऐसे लेख का पुनर्विक्रय मूल्य कम हो जाता है। "या" शब्द का उपयोग इसे स्पष्ट करता है कि भारत को निर्यात मूल्य में गिरावट के साथ तीनों शर्तों में से किसी एक की संतुष्टि अवशोषण स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। नीचे की गई जांच तदनुसार की जाती है।

अवशोषण अवधि के दौरान विषय वस्तु का लेन-देन-वार आयात

19. अवशोषण अवधि के लिए डीजी सिस्टम्स से प्राप्त लेन-देन-वार डेटा विषय देश से विषय वस्तु के निम्नलिखित आयातों को दर्ज करता है।

क्रम संख्या	बीई दिनांक	सीटीएच	मात्रा (किग्रा)	निर्धारण योग्य मूल्य (₹)	CIF (₹/किग्रा)	CIF ($/किग्रा)
1	***	38089390	15,000	***	***	15–16
2	***	38089399	5,000	***	***	5–6
3	***	38089399	23,000	***	***	15–16
4	***	38089399	23,000	***	***	15–16
कुल			**66,000**			

स्रोत: डीजी सिस्टम्स लेन-देन-वार डेटा। 87.26 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर की दर से परिवर्तित मूल्य।

20. अथॉरिटी ऊपर दिए गए डेटा से ये बातें नोट करती है। पहला, एब्जॉर्प्शन पीरियड के दौरान इम्पोर्ट किए गए संबंधित सामान की कुल मात्रा 66 मीट्रिक टन है। दूसरा, एस.एन. 1 पर मौजूद कंसाइनमेंट को 8 मई 2025 को एंटी-डंपिंग ड्यूटी लागू होने से पहले, *** अप्रैल 2025 को क्लियर किया गया था; ड्यूटी लागू होने के बाद की मात्रा 51 मीट्रिक टन है। तीसरा और महत्वपूर्ण बात यह है कि एस.एन.1, 3 और 4 पर मौजूद कंसाइनमेंट मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस के आस-पास की सीआईएफ वैल्यू पर आए थे, जबकि एस.एन. 2 पर मौजूद 5 मीट्रिक टन का कंसाइनमेंट ऐसी सीआईएफ वैल्यू पर आया था जो अन्य कंसाइनमेंट के लेवल का लगभग 38% था। एस.एन.1, 3 और 4 पर मौजूद कंसाइनमेंट पार्टिसिपेट करने वाले एक्सपोर्टर से जवाब देने वाले इम्पोर्टर्स में से एक द्वारा इम्पोर्ट किए गए थे; एस.एन. 2 पर मौजूद कंसाइनमेंट ऐसे

इम्पोर्टर द्वारा इम्पोर्ट किया गया था जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और यह संबंधित देश के ऐसे एक्सपोर्टर से आया था जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था।

21. चौथी बात, रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि संबंधित सामान से प्रोड्यूसर को जो असल कमाई हुई, वह उस कीमत से काफी कम थी जिस पर वे सामान भारत को एक्सपोर्ट किए गए और भारत में इम्पोर्ट के समय उनकी कीमत बताई गई। वेरिफिकेशन के जवाब में, शामिल पार्टियों ने प्रोड्यूसर के ग्रुप ट्रांसफर इनवॉइस पेश किए। इन इनवॉइस की पुष्टि प्रोड्यूसर के ईआरपी सिस्टम में उसी समय की गई एंट्रीज़ से होती है। इनसे पता चलता है कि प्रोड्यूसर, मेसर्स ज़ियांगशुई झोंगशान बायोसाइंस कंपनी लिमिटेड ने संबंधित एक्सपोर्टर, मेसर्स झेजियांग झोंगशान केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड (एक ग्रुप कंपनी) को ये सामान बेचे थे। इस बिक्री से 'एक्स-वर्क्स' आधार पर मिली रकम लगभग *** से *** USD प्रति किलोग्राम थी। उन्हीं सामानों के लिए संबंधित एक्सपोर्टर ने भारत को एक्सपोर्ट करने के वास्ते इनवॉइस बनाए और भारतीय कस्टम्स के सामने सीआईएफ आधार पर उनकी कीमत लगभग 15.0 से 15.2 USD प्रति किलोग्राम बताई। इसलिए, शामिल पार्टियों के अपने वेरिफाइड रिकॉर्ड के आधार पर, जिस कीमत पर प्रोड्यूसर ने वे सामान बेचे, वह भारत में इम्पोर्ट के समय बताई गई कीमत का लगभग 35% से 45% थी।

22. अथॉरिटी इस बात से वाकिफ़ है कि यह 'एक्स-वर्क्स' ट्रांज़ैक्शन (कारखाने से सीधे बिक्री का सौदा) एक ही ग्रुप की संबंधित कंपनियों के बीच हुआ है और यह अपने आप में 'आर्म्स-लेंथ प्राइस' (स्वतंत्र बाज़ार मूल्य) नहीं है जिसे सामान्य मूल्य या निर्यात मूल्य माना जा सके, और न ही इसे ऐसा माना गया है। हालाँकि, यह इसमें शामिल पार्टियों का अपना समकालीन और सत्यापित रिकॉर्ड है, और यह दो वजहों से महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि भारत में आयात के समय घोषित मूल्य को 'न्यूनतम आयात मूल्य' (एमआईपी) या उसके आस-पास बनाए रखा गया था, जबकि उत्पादक को असल में उससे काफी कम कीमत मिल रही थी; और, यह आवेदकों द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए स्वतंत्र 'चीन कस्टम्स' के निर्यात डेटा और एस.एन. 2 पर मौजूद एमआईपी से कम कीमत वाले कंसाइनमेंट (माल की खेप) से काफी हद तक मेल खाता है। इससे इस निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि एब्जॉर्प्शन पीरियड (कीमत सोखने की अवधि) के दौरान भारत में संबंधित सामान की प्रभावी कीमत घोषित आयात मूल्यों से काफी कम थी और लागू ड्यूटी (शुल्क) का सुधारात्मक असर कमज़ोर पड़ गया था।

न्यूनतम आयात मूल्य पर निर्भरता और वास्तविक निर्यात मूल्य

23. अन्य हितधारकों ने तर्क दिया है कि भारतीय सीमा शुल्क डेटा में परिलक्षित आयात मूल्यों में कोई गिरावट नहीं दिखती है, और घरेलू उद्योग ने पूरी अवशोषण अवधि के दौरान एमआईपी संरक्षण का आनंद लिया। प्राधिकारी ने नोट किया कि अधिनियम की धारा 9ए(1बी) के साथ पठित नियम 29 के तहत एक अवशोषण जांच का उद्देश्य यह जांचना है कि क्या निर्यातकों ने एंटी-डंपिंग शुल्क के प्रभाव को अवशोषित करने के लिए शुल्क लगाए जाने के बाद अपने वास्तविक निर्यात मूल्यों में कमी की है। ऐसी जांच के लिए आवश्यक रूप से निर्यातकों द्वारा वसूले गए वास्तविक निर्यात मूल्यों का निर्धारण आवश्यक है, न कि अन्य नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए घोषित मूल्यों का। पैराग्राफ 19 से 21 में दर्ज कारणों के लिए, प्राधिकारी ने चीन सीमा शुल्क निर्यात डेटा द्वारा पुष्टि किए जाने पर, न्यूनतम आयात मूल्य के बंधन से मुक्त दाखिल हुए माल की कीमत को भारत को विषय वस्तु की वास्तविक निर्यात मूल्य निर्धारण के प्रतिनिधि के रूप में अपनाया है। एमआईपी (न्यूनतम आयात मूल्य) का मात्र अस्तित्व ही अंतिम एंटी-डंपिंग शुल्क के अवशोषण के निष्कर्ष को रोकता नहीं है।

24. अन्य हितधारकों ने तर्क दिया है कि एमआईपी से नीचे साफ किया गया कोई भी आयात सीमा शुल्क/डीजीएफटी प्रवर्तन का मामला है, न कि प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र के भीतर अवशोषण का साक्ष्य। प्राधिकारी ने नोट किया कि डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित एमआईपी और अधिनियम की धारा 9ए के तहत लगाया गया एंटी-डंपिंग शुल्क अलग-अलग वैधानिक शासनों के तहत काम करने वाले अलग-अलग साधन हैं। एंटी-डंपिंग शुल्क के अवशोषण की जांच धारा 9ए(1बी) के साथ पठित नियम 29 के तहत प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आती है। वास्तविक निर्यात मूल्यों पर निर्भरता निर्यातकों के मूल्य निर्धारण व्यवहार की जांच के सीमित उद्देश्य के लिए है, और एमआईपी का प्रवर्तन नहीं है। तर्क स्वीकार नहीं किया जाता है।

25. प्राधिकारी ने भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा दायर वाणिज्यिक चालान और संबंधित सीमा शुल्क निर्यात घोषणाओं पर अलग से विचार किया है, जो ऊपर अपनाई गई कीमत से भौतिक रूप से ऊपर सीआईएफ आधार पर घोषित मूल्यों को दर्ज करते हैं। वे घोषित मूल्य पैराग्राफ 19 की तालिका के क्र.सं. 1, 3 और 4 पर माल के अनुरूप हैं, जो एमआईपी के क्षेत्र में साफ किए गए थे, और ऊपर दर्ज कारणों के लिए ऐसे घोषित मूल्य एक अलग नियामक आवश्यकता के अनुपालन को दर्शाते हैं, न कि वास्तविक निर्यात मूल्य निर्धारण व्यवहार को। भाग लेने वाले निर्यातकों ने अपनी उत्पादन लागत, या अपने तीसरे देशों को लेन-देन-वार निर्यात मूल्य रिकॉर्ड पर नहीं

रखे हैं, और न ही उन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा किया है; इसलिए उन्होंने प्राधिकारी के समक्ष कोई सत्यापनीय सामग्री नहीं रखी है जो अपनाई गई कीमत को विस्थापित कर सके।

उत्पादन लागत में गतिविधि

26. अन्य हितधारकों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत पर निर्भर नहीं किया जा सकता है, और नियम 29 के लिए निर्यात करने वाले देश में उत्पादन लागत की जांच आवश्यक है। प्राधिकारी ने नोट किया कि मूल जांच में, चीनी उत्पादकों को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के तहत काम करने वाला माना गया था। वर्तमान जांच में, भाग लेने वाले निर्यातकों ने न तो बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा किया है और न ही बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली दायर की है। इसलिए प्राधिकारी यह जांचने के लिए निर्यातकों के लागत डेटा पर निर्भर रहने में असमर्थ है कि क्या निर्यात कीमतों में गिरावट उनकी उत्पादन लागत में किसी भी गिरावट के अनुरूप है। निर्यातकों से सत्यापनीय लागत जानकारी के अभाव में, और मूल जांच में अपनाई गई गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पद्धति के अनुरूप, प्राधिकारी ने उत्पादन लागत में परिवर्तन के लिए एक सरोगेट के रूप में विषय वस्तु के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख कच्चे माल की वैश्विक स्तर पर प्रचलित कीमतों में गतिविधि की जांच की है। प्रासंगिक जानकारी नीचे दी गई है।

क्रम संख्या	**विवरण**	**इकाई**	**जनवरी 2023–दिसंबर 2023**	**जनवरी 2025–सितंबर 2025**
1	**एसीटिक एसिड**	₹/किग्रा	***	***
	रुझान	सूचकांकित	100	84
2	**एक्रोलिन टेक्निकल**	₹/किग्रा	***	***
	रुझान	सूचकांकित	100	98
3	**अमोनिया घोल 24%**	₹/किग्रा	***	***
	रुझान	सूचकांकित	100	107
4	**कॉस्टिक सोडा लाइ (32%)**	₹/किग्रा	***	***
	रुझान	सूचकांकित	100	102
5	**हाइड्रोजन पाइपलाइन**	₹/किग्रा	***	***
	रुझान	सूचकांकित	100	101

6	**तरल क्लोरीन पाइपलाइन**	₹/किग्रा	***	***
	रुझान	सूचकांकित	100	122
7	**मैग्नीशियम टर्निंग्स**	₹/किग्रा	***	***
	रुझान	सूचकांकित	100	78
8	**मेथनॉल**	₹/किग्रा	***	***
	रुझान	सूचकांकित	100	112
9	मिथाइल क्लोराइड	₹/kg	***	***
	रुझान	सूचकांकित	100	88
10	फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड	₹/kg	***	***
	रुझान	सूचकांकित	100	80
11	सोडियम साइनाइड	₹/kg	***	***
	रुझान	सूचकांकित	100	87
12	ट्राइएथिल फॉस्फाइट	₹/kg	***	***
	रुझान	सूचकांकित	100	91
	कुल	₹/kg	***	***
	रुझान	सूचकांकित	100	93

27. यह देखा गया है कि प्रासंगिक कच्चे माल की कीमतों का कुल योग अवशोषण अवधि के दौरान लगभग 101 रुपये प्रति किग्रा (*** रुपये/किग्रा से *** रुपये/किग्रा तक) घट गया है, अर्थात लगभग 7.4% की कमी।

भारत को निर्यात मूल्य में गतिविधि

28. यह जांचने के लिए कि क्या एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने के बाद निर्यात मूल्यों में कमी आई है, प्राधिकारी ने मूल जांच अवधि के दौरान भारत को विषय वस्तु के निर्यात मूल्य की तुलना पैराग्राफ 19 से 22 में निर्धारित अवशोषण अवधि के दौरान वास्तविक निर्यात मूल्य से की है। शुद्ध निर्यात मूल्य सीआईएफ मूल्य से नीचे दी गई कटौतियाँ करके प्राप्त किया गया है, ताकि मूल्य को कारखाना स्तर पर लाया जा सके।

क्रम संख्या	**विवरण**	**माप की इकाई**	**₹/किग्रा**	**$/किग्रा**

1	**CIF मूल्य**	₹/किग्रा	***	***
2	घटाएँ: **समुद्री माल भाड़ा**	₹/किग्रा	***	***
3	घटाएँ: **समुद्री बीमा @ 0.05%**	₹/किग्रा	***	***
4	**FOB मूल्य**	₹/किग्रा	***	***
5	घटाएँ: **कमीशन @ 3%**	₹/किग्रा	***	***
6	घटाएँ: **बैंक शुल्क @ 0.5%**	₹/किग्रा	***	***
7	घटाएँ: **बंदरगाह व्यय @ 0.5%**	₹/किग्रा	***	***
8	घटाएँ: **हैंडलिंग व्यय @ 0.5%**	₹/किग्रा	***	***
9	**शुद्ध निर्यात मूल्य**	₹/किग्रा	***	***

विनिमय दर: 87.26 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर।

29. उपरोक्त आधार पर, अवशोषण अवधि के दौरान भारत को विषय वस्तु का शुद्ध निर्यात मूल्य *** अमेरिकी डॉलर प्रति किग्रा की सीमा में है, जबकि मूल जांच में निर्धारित शुद्ध निर्यात मूल्य *** अमेरिकी डॉलर प्रति किग्रा की सीमा में था। एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने के बाद निर्यात मूल्य में तदनुसार लगभग 46% की गिरावट आई है। उपरोक्त गणना में लागू *** प्रति मीट्रिक टन का समुद्री माल भाड़ा रिकॉर्ड पर मौजूद शिपिंग दस्तावेजों से निर्धारित किया गया है। अन्य हितधारकों ने तर्क दिया है कि गिरावट, यदि कोई है, भारतीय रुपये के अवमूल्यन के कारण है। प्राधिकारी ने नोट किया कि निर्यात मूल्य अमेरिकी डॉलर में उद्धृत है, और गिरावट अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में स्पष्ट है; इसलिए, गिरावट को विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। चूंकि निर्यात मूल्य एक ही मुद्रा में व्यक्त और तुलना की जाती है, निर्यातक यह दावा नहीं कर सकते हैं कि गिरावट रुपये के अवमूल्यन का परिणाम है।

तीसरे देशों को निर्यात मूल्य

30. अन्य हितधारकों ने तर्क दिया है कि भारत को निर्यात मूल्य में गिरावट तीसरे देशों को निर्यात मूल्य में गिरावट के अनुरूप है, और इसलिए नियम 29 संतुष्ट नहीं है। प्राधिकारी ने नोट किया कि, पहला, भाग लेने वाले निर्यातकों ने इस दावे को प्रमाणित करने के लिए तीसरे देशों को कोई लेन-देन-वार निर्यात डेटा रिकॉर्ड पर नहीं रखा है, और तर्क तदनुसार अप्रमाणित रहता है। दूसरा, और किसी भी स्थिति में, नियम 29(1) वियोज्य है: भारत को निर्यात मूल्य में गिरावट के साथ उत्पादन लागत में अनुरूप परिवर्तन की अनुपस्थिति, अपने आप में, अवशोषण स्थापित करने के लिए पर्याप्त है,

तीसरे देशों की कीमतों की गतिविधि से स्वतंत्र। जैसा कि ऊपर स्थापित किया गया है, भारत को निर्यात मूल्य में लगभग 46% की गिरावट आई, जबकि प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में केवल लगभग 7.4% की कमी आई। इसलिए निर्यात मूल्य में गिरावट उत्पादन लागत में परिवर्तन के अनुरूप नहीं है, और नियम 29(1) के पहले खंड के तहत शर्त पूरी होती है। तर्क तदनुसार स्वीकार नहीं किया जाता है।

31. प्राधिकारी ने अवशोषण अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य में विचाराधीन उत्पाद का वास्तविक लेन-देन मूल्य क्या था, इसकी जांच की है। तीन स्वतंत्र स्रोत एकत्रित होते हैं: आवेदक के चीनी उत्पादकों और व्यापारियों के चालान, जो 5.50–6.10 अमेरिकी डॉलर/किग्रा की सीमा में एफओबी मूल्य दिखाते हैं; आवेदक द्वारा भरोसा किया गया चीनी सीमा शुल्क निर्यात डेटा, जो 5.50–6.00 अमेरिकी डॉलर/किग्रा की सीमा में एक भारित औसत एफओबी मूल्य दिखाता है; और भाग लेने वाले निर्यातक की अपनी परिशिष्ट-1, जो 5.50–6.00 अमेरिकी डॉलर/किग्रा की सीमा में घरेलू बाजार प्राप्ति की रिपोर्ट करती है। निर्यातक ने स्वयं कहा है कि चीन में बेचा गया लेख और भारत को निर्यात किया गया लेख समान गुणवत्ता और पैकिंग के हैं, और विशेषताओं या बिक्री की शर्तों में किसी अंतर का साक्ष्य नहीं दिया गया है। प्राधिकारी तदनुसार इसे स्थापित मानता है कि अवशोषण अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य में विचाराधीन उत्पाद 5.50–6.10 अमेरिकी डॉलर/किग्रा की सीमा में बेचा गया था। यह निष्कर्ष केवल मूल्य स्तर से संबंधित है; सामान्य मूल्य मूल जांच में अपनाए गए आधार पर जारी है; निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार से इनकार कर दिया है।

भारत में पुनर्विक्रय मूल्य

32. अन्य हितधारकों ने तर्क दिया है कि आवेदकों ने भारत में विषय वस्तु के पुनर्विक्रय मूल्यों से संबंधित कोई डेटा प्रस्तुत नहीं किया है। प्राधिकारी ने नोट किया कि, नियम 29(1) का पहला खंड ऊपर दर्ज कारणों के लिए संतुष्ट होने के कारण, और प्रावधान वियोज्य होने के कारण, यह आवश्यक नहीं है कि पुनर्विक्रय-मूल्य खंड स्वतंत्र रूप से संतुष्ट हो। प्राधिकारी ने फिर भी रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की जांच की है। दो आयातकों, अर्थात् झोंगशान क्रॉप साइंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और टेफ्रा बायोसाइंस एलएलपी ने भारत में विषय वस्तु के आयात और पुनर्विक्रय के विवरण वाले प्रश्नावली का जवाब दायर किया है। दायर किए गए डेटा पर, अवशोषण अवधि के दौरान भारत में आयातित विषय वस्तु के पुनर्विक्रय मूल्य संबंधित भूमि मूल्यों से ऊपर हैं, और अवशोषण अवधि में पुनर्विक्रय मूल्यों में कोई गिरावट का रुझान नहीं दिखता है। प्राधिकारी आगे नोट करता है कि रिकॉर्ड पर मौजूद पुनर्विक्रय डेटा एमआईपी के क्षेत्र में साफ किए गए माल से संबंधित है, और पैराग्राफ 19 की तालिका

के क्र.सं. 2 पर माल तक विस्तारित नहीं है, जिसके आयातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है।

जांच अवधि और आयात की मात्रा

33. अन्य हितधारकों ने तर्क दिया है कि नियम 29 को केवल शुल्क लगाए जाने के बाद ही लागू किया जा सकता है, और 9-माही अवशोषण अवधि के भीतर शुल्क-पूर्व अवधि को शामिल करना एक अधिकार क्षेत्रीय त्रुटि है। प्राधिकारी ने नोट किया कि अवशोषण का विश्लेषण 8 मई 2025 को एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने के बाद निर्यातकों के वास्तविक निर्यात मूल्य निर्धारण व्यवहार पर निर्भर करता है। जैसा कि पैराग्राफ 19 की तालिका से पता चलता है, शुद्ध निर्यात मूल्य के निर्धारण के लिए भरोसा किया गया माल जुलाई 2025 को साफ किया गया था, अर्थात शुल्क लगाए जाने के बाद; और शुल्क-पश्चात् आयात की मात्रा कुल 66 मीट्रिक टन में से 51 मीट्रिक टन है। इसलिए निर्यात मूल्य में गिरावट का निष्कर्ष शुल्क-पूर्व लेन-देन पर निर्भर नहीं है, और अवशोषण की वर्णनात्मक अवधि के भीतर पहले के महीनों को शामिल करना विश्लेषण को दोषपूर्ण नहीं बनाता है। तर्क, तदनुसार, स्वीकार नहीं किया जाता है।

34. अन्य हितधारकों ने तर्क दिया है कि अवशोषण-अवधि की कीमतों की मूल पीओआई से तुलना करने का कोई कानूनी आधार नहीं है, और 9-माही अवधि मनमानी है क्योंकि नियम 5(3ए)(ii) एक सामान्य 12-माही पीओआई निर्धारित करता है। प्राधिकारी ने नोट किया कि नियम 29(1) स्वयं "एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने के बाद" निर्यात मूल्य की तुलना उस आधार से करने की परिकल्पना करता है जिस पर शुल्क मूल रूप से निर्धारित किया गया था; ऐसी तुलना के लिए आवश्यक रूप से मूल जांच अवधि के निर्यात मूल्य को बेंचमार्क के रूप में आवश्यकता होती है, क्योंकि लागू शुल्क उस अवधि में प्रचलित स्थितियों पर निर्धारित किया गया था। जहां तक जांच अवधि का संबंध है, नियम 29 एक अवशोषण समीक्षा के लिए एक निश्चित पीओआई निर्धारित नहीं करता है; अवधि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित की जा सकती है, और प्राधिकारी ने 9-माही अवधि अपनाने के अपने कारण आरंभ अधिसूचना में दर्ज किए। नियम 5(3ए)(ii) मूल जांच के लिए जांच अवधि को नियंत्रित करता है और अपने आप में नियम 29 के तहत उपलब्ध विवेक को सीमित नहीं करता है। तर्क स्वीकार नहीं किया जाता है।

35. अन्य हितधारकों ने तर्क दिया है कि कम कीमत पर आयात की मात्रा इतनी कम है कि यह स्थापित नहीं कर सकती कि शुल्क अप्रभावी हो गया था। प्राधिकारी खुलकर

स्थिति दर्ज करता है: शुल्क लगाए जाने के बाद आयातित 51 मीट्रिक टन में से, 5 मीट्रिक टन, या लगभग 10%, कम कीमत पर दाखिल हुआ, शेष न्यूनतम आयात मूल्य के क्षेत्र में साफ किया गया। प्राधिकारी नोट करता है, हालांकि, नियम 29 निर्यातकों के मूल्य निर्धारण व्यवहार पर और क्या ऐसा व्यवहार एंटी-डंपिंग शुल्क को अप्रभावी बनाता है, पर निर्देशित है, न कि आयात की किसी सीमा मात्रा पर; न तो धारा 9ए(1बी) और न ही नियम 29 कोई न्यूनतम मात्रा निर्धारित करता है। क्र.सं. 2 पर माल का महत्व उसकी मात्रा में नहीं है, बल्कि इस तथ्य में है कि यह अवशोषण अवधि के दौरान एकमात्र माल है जो न्यूनतम आयात मूल्य के बंधन से मुक्त दाखिल हुआ, और यह ऐसी कीमत पर दाखिल हुआ जिस पर 2,998 अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन का एंटी-डंपिंग शुल्क काफी हद तक निष्प्रभावी हो जाता है, जो कि भौतिक रूप से बड़ी मात्रा को कवर करने वाले चीन सीमा शुल्क निर्यात डेटा के अनुरूप है। प्राधिकारी के विचार में उस कीमत पर आयात की मात्रा, निर्यातकों के मूल्य निर्धारण व्यवहार के बजाय लागू एमआईपी का एक कार्य है, और समवर्ती उपाय में किसी भी ढील पर बढ़े हुए हानिकारक आयातों की संभावना का संकेत है। तर्क स्वीकार नहीं किया जाता है।

अवशोषण पर विश्लेषण

36. उपरोक्त के आलोक में, प्राधिकारी नोट करता है कि जबकि कच्चे माल की कीमतों (लगभग 7.4% तक) और सरोगेट उत्पादन लागत में मामूली कमी आई है, भारत को विषय वस्तु का निर्यात मूल्य एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने के बाद लगभग 46% कम हो गया है। इस प्रकार निर्यात मूल्य में गिरावट उत्पादन लागत में परिवर्तन से कहीं अधिक है, और उसके अनुरूप नहीं है। नीचे दी गई तालिका निर्यातकों द्वारा अवशोषण की डिग्री का सारांश प्रस्तुत करती है।

क्रम संख्या	**विवरण**	**माप की इकाई**	**पीओआई – ओआई**	**पीओआई – एबी**
1	**भारत को शुद्ध निर्यात मूल्य (रुझान, सूचकांकित)**	सूचकांकित	100	54
2	**कच्चे माल की लागत (रुझान, सूचकांकित)**	सूचकांकित	100	93

37. प्राधिकारी, तदनुसार, नोट करता है कि विषय देश से विषय वस्तु का निर्यात मूल्य एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने के बाद उत्पादन लागत में किसी अनुरूप परिवर्तन के

बिना कम हो गया है। नियम 29(1) के तहत अवशोषण की शर्त इसलिए पूरी होती है। प्राधिकारी ने नियम 29(2) के अनुसार डंपिंग मार्जिन और चोट मार्जिन का पुनर्मूल्यांकन किया है, जैसा कि नीचे खंड E.3 में निर्धारित किया गया है।

डंपिंग मार्जिन और चोट मार्जिन का पुनर्मूल्यांकन

38. एंटी-डंपिंग नियमों का नियम 29(2) निम्नलिखित प्रावधान करता है:

> *"(2) जहां एंटी-डंपिंग शुल्क के अधीन कोई लेख ऐसी कीमत पर या ऐसी शर्तों के तहत भारत में आयात किया जाता है जिसे मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क का अवशोषण माना जाता है, और ऐसा शुल्क इस प्रकार अप्रभावी हो जाता है या हो सकता है, वहाँ नामित प्राधिकारी, समीक्षा करने के बाद, डंपिंग मार्जिन और चोट मार्जिन का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद एंटी-डंपिंग शुल्क के रूप या आधार, या एंटी-डंपिंग शुल्क की मात्रा, या दोनों में संशोधन की सिफारिश कर सकता है, और पहले से निर्धारित सामान्य मूल्य और चोट में उचित परिवर्तन या समायोजन, यदि आवश्यक हो, क्रमशः नियम 10 और इन नियमों के अनुलग्नक III के प्रावधानों के अनुसार किए जा सकते हैं।"*

39. प्राधिकारी ने नोट किया कि नियम 29(2) "पहले से निर्धारित सामान्य मूल्य और चोट में ... उचित परिवर्तन या समायोजन" करने की परिकल्पना करता है। इस शक्ति के प्रयोग में प्राधिकारी ने अवशोषण अवधि के लिए नियम 10 और क्रमशः अनुलग्नक III के अनुसार निर्मित सामान्य मूल्य और गैर-हानिकारक मूल्य का पुनर्मूल्यांकन किया है। दोबारा आंकी गई गैर-हानिकारक मूल्य, शुरुआती जांच में तय गैर-हानिकारक मूल्य, से लगभग 14% कम है। इसकी मुख्य वजह कच्चे माल की लागत में आई कमी है, जो लगभग 19% है। चूंकि चीनी उत्पादकों ने मूल जांच के समय बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा नहीं किया था, और भाग लेने वाले निर्यातकों ने वर्तमान कार्यवाही में ऐसा उपचार का दावा नहीं किया है, निर्मित सामान्य मूल्य नियमों के अनुलग्नक-I के पैरा-7 के तहत मूल जांच में अपनाई गई पद्धति के अनुसार निर्धारित किया गया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को चोट का कोई ताजा निर्धारण नहीं किया है, मूल जांच का चोट निर्धारण अवशोषण समीक्षा में फिर से नहीं खोला जा रहा है।

40. अवशोषण अवधि के लिए पुनर्मूल्यांकित निर्मित सामान्य मूल्य निम्नानुसार है।

क्रम संख्या	**विवरण**	**इकाई**	**पीओआई – ओआई**	**पीओआई – एबी**
1	**निर्मित सामान्य मूल्य**	$/किग्रा	***	***

2	**विनिमय दर**	₹/$	83.52	87.26

41. अवशोषण अवधि के लिए पुनर्मूल्यांकित गैर-हानिकारक मूल्य निम्नानुसार है।

क्रम संख्या	**विवरण**	**इकाई**	**पीओआई – ओआई**	**पीओआई – एबी**
1	**गैर-हानिकारक मूल्य**	$/किग्रा	***	***
2	**विनिमय दर**	₹/$	83.52	87.26

42. पुनर्मूल्यांकित निर्मित सामान्य मूल्य और पैराग्राफ 27 में निर्धारित विषय वस्तु के शुद्ध निर्यात मूल्य पर विचार करते हुए, चीन जनवादी गणराज्य से विषय वस्तु के लिए डंपिंग मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

क्रम संख्या	**विवरण**	**निर्मित सामान्य मूल्य ($/किग्रा)**	**शुद्ध निर्यात मूल्य ($/किग्रा)**	**डंपिंग मार्जिन ($/किग्रा)**	**डंपिंग मार्जिन सीमा (%)**
1	**मूल अवधि**	***	***	***	20–30%
2	**अवशोषण अवधि**	***	***	***	85–95%

43. यह देखा गया है कि भारत को शुद्ध निर्यात मूल्य मूल अवधि से अवशोषण अवधि तक काफी कम हो गया है, और शुद्ध निर्यात मूल्य में गिरावट पुनर्मूल्यांकित निर्मित सामान्य मूल्य में गिरावट से अधिक तीव्र है। परिणामस्वरूप, डंपिंग मार्जिन मूल अवधि के दौरान 20–30% की सीमा से बढ़कर अवशोषण अवधि के दौरान 85–95% की सीमा तक पहुंच गया है, अर्थात लगभग तीन गुना वृद्धि। अब निर्धारित डंपिंग मार्जिन उस राशि से *** अधिक है, जो स्थापित करता है कि लागू एंटी-डंपिंग शुल्क निर्यातकों द्वारा निर्यात मूल्य में कमी के माध्यम से अवशोषित कर लिया गया है और अब पाई गई डंपिंग की भरपाई नहीं करता है।

44. इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि डंपिंग मार्जिन बढ़ गया है।

45. विषय वस्तु के पुनर्मूल्यांकित गैर-हानिकारक मूल्य और भूमि मूल्य पर विचार करते हुए, चीन जनवादी गणराज्य से विषय वस्तु के लिए चोट मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

क्रम संख्या	विवरण	एनआईपी ($/किग्रा)	उतरित मूल्य ($/किग्रा)	क्षति मार्जिन ($/किग्रा)	क्षति मार्जिन सीमा (%)
1	**मूल अवधि**	***	***	***	20–30%
2	**अवशोषण अवधि**	***	***	***	85–95%

46. यह देखा गया है कि विषय आयात का भूमि मूल्य मूल अवधि के दौरान *** अमेरिकी डॉलर प्रति किग्रा से घटकर अवशोषण अवधि के दौरान *** अमेरिकी डॉलर प्रति किग्रा हो गया है, जो लगभग 45% की कमी है, जबकि पुनर्मूल्यांकित गैर-हानिकारक मूल्य में लगभग 18% की कमी आई है। परिणामस्वरूप, चोट मार्जिन मूल अवधि के दौरान 20–30% की सीमा से बढ़कर अवशोषण अवधि के दौरान 85–95% की सीमा तक पहुंच गया है। विषय आयात का भूमि मूल्य लागू एंटी-डंपिंग शुल्क को ध्यान में रखने के बाद भी गैर-हानिकारक मूल्य से काफी नीचे बना हुआ है, जो पुष्टि करता है कि शुल्क का उपचारात्मक प्रभाव कमजोर हो गया है।

47. आयात का भूमि मूल्य प्राधिकारी की सुसंगत प्रथा के अनुसार, मूल्यांकन योग्य मूल्य के साथ-साथ लागू सीमा शुल्कों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

48. इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि चोट का अंतर बढ़ गया है।

6. खुलासे के बाद की टिप्पणियाँ

च.1 अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा दी गई जानकारी/टिप्पणियाँ

49. इच्छुक पक्षों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ दर्ज की गई हैं।

i. एक्सपोर्ट की कीमतों में गिरावट का कारण ग्लुफोसिनेट की कीमतों में वैश्विक गिरावट को बताया गया, न कि एंटी-डंपिंग ड्यूटी के अवशोषण (absorption) को।

ii. अवशोषण का निर्धारण एक्सपोर्टर-वार किया जाना चाहिए, और किसी अलग-अलग एक्सपोर्टर के खिलाफ अवशोषण साबित करने के लिए देश-व्यापी डेटा या भाग न लेने वाले एक्सपोर्टर के लेन-देन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

iii. ड्यूटी लगने के बाद हुए कुल 51 MT इम्पोर्ट में से केवल 5 MT कम कीमत पर थे; इतने सीमित और इक्का-दुक्का इम्पोर्ट से यह साबित नहीं हो सकता कि ड्यूटी बेअसर हो गई थी।

iv. 5 MT वाले लेन-देन को विशेष रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह प्रतिनिधि (representative) नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें भाग न लेने वाला एक्सपोर्टर शामिल था और यह MIP फ्रेमवर्क के दायरे से बाहर था।

v. ड्यूटी लगने के बाद का केवल लगभग चार महीने का डेटा उपलब्ध था, जिसे अवशोषण का निर्धारण करने के लिए अपर्याप्त बताया गया।

vi. MIP के कामकाज का हवाला देते हुए यह तर्क दिया गया कि वास्तविक मूल्य निर्धारण व्यवहार का आकलन करने के लिए MIP-अनुपालन वाले लेन-देन पर विचार किया जाना चाहिए, न कि MIP से कम कीमत वाले इक्का-दुक्का इम्पोर्ट पर।

vii. इस दृष्टिकोण को DGTR की पिछली कार्यप्रणाली के असंगत बताया गया, जिसमें एक्सपोर्टर-विशिष्ट सबूत की आवश्यकता होती थी।

viii. नियम 2(b), नियम 5(3A) (ii) की प्रयोज्यता और अवशोषण के निष्कर्ष के लिए एक्सपोर्टर-विशिष्ट सबूत की आवश्यकता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया।

ix. मूल निष्कर्षों पर चुनिंदा रूप से निर्भरता को चुनौती दी गई, विशेष रूप से कीमतों में वैश्विक गिरावट की कथित अनदेखी को।

x. संभावित संबंध/इम्पोर्ट के आधार पर DI के रूप में UPL की नियम 2(b) पात्रता पर सवाल उठाया गया और सत्यापन का अनुरोध किया गया।

xi. ड्यूटी में प्रस्तावित संशोधन/पिछली तारीख से लागू करने (पिछली तारीख से लागू होना) को भी चुनौती दी गई।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा दी गई जानकारी/टिप्पणियाँ

50. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ दर्ज की गई हैं।

i. मुख्य कच्चे माल की कीमतों में केवल 7.4% की गिरावट के मुकाबले एक्सपोर्ट की कीमत में 46% की गिरावट यह दर्शाती है कि एक्सपोर्ट की कीमत में कमी उत्पादन लागत में कमी के अनुपात में नहीं थी और इसलिए नियम 29(1) के तहत अवशोषण साबित होता है।

ii. एक्सपोर्ट की कीमत में गिरावट USD और INR दोनों ही रूपों में स्पष्ट है; इसलिए, यह तर्क कि गिरावट रुपये की कीमत घटने के कारण हुई, सही नहीं है।

iii. नियम 29(1) एब्जॉर्प्शन (लागत सोखने) के लिए तीन विकल्प देता है; इनमें से किसी एक शर्त का पूरा होना ही काफी है, तीनों शर्तों का एक साथ पूरा होना ज़रूरी नहीं है।

iv. कीमतों में वैश्विक गिरावट का मतलब यह नहीं है कि एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, क्योंकि मुख्य बात यह है कि क्या भारत को किए गए निर्यात की कीमत में कमी, उत्पादन लागत में बदलाव के अनुपात में थी; इस मामले में, निर्यात कीमत में गिरावट कच्चे माल की लागत में गिरावट से कहीं ज़्यादा थी।

v. आयात की कम मात्रा एब्जॉर्प्शन को नहीं रोकती; मुख्य बात कीमत तय करने का तरीका है और यह देखना है कि क्या इससे ड्यूटी का सुधारात्मक असर कम हो रहा है। इसलिए, एमआईपी से कम कीमत वाले 5 मीट्रिक टन आयात भी महत्वपूर्ण हैं।

vi. 5 मीट्रिक टन के लेन-देन को सिर्फ़ इसलिए नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि इसकी मात्रा कम थी; निर्यातक यह साबित करने के लिए सबूत नहीं दे पाया कि एमआईपी के नियमों के अनुसार तय की गई कीमतें उसके स्वतंत्र मूल्य निर्धारण का नतीजा थीं।

vii. एमआईपी और एंटी-डंपिंग शुल्क अलग-अलग उपाय हैं। एमआईपी का पालन करने से वास्तविक निर्यात कीमतों की जांच नहीं रुकती, और एमआईपी एक प्रभावी एंटी-डंपिंग शुल्क की जगह नहीं ले सकता।

viii. जनवरी-सितंबर 2025 की एब्जॉर्प्शन अवधि सही है, क्योंकि नियम 29 में ड्यूटी के बाद की न्यूनतम अवधि तय नहीं की गई है; इसके अलावा, जिन लेन-देन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया, वे 8 मई 2025 को एंटी-डंपिंग शुल्क लागू होने के बाद हुए थे।

ix. कल्याणी स्टील्स और नियम 5(3A) (ii) पर निर्भरता को गलत बताया गया क्योंकि मौजूदा समीक्षा नियम 29 और 30 के तहत होती है और नियम 29 में शुरुआती जांच के लिए ज़रूरी 12 महीने की पीओआई (जांच की अवधि) की शर्त लागू नहीं होती है।

x. निर्यात कीमत तय करने के लिए चीन के कस्टम्स डेटा पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह उस कीमत को दिखाता है जिस पर सामान निर्यात किया गया था, जबकि भारतीय CIF वैल्यू में एमआईपी के नियमों के अनुसार घोषित वैल्यू हो सकती है, न कि वास्तविक निर्यात कीमत।

xi. जहां निर्यातक के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जाती है, वहां अथॉरिटी नियम 6(8) के तहत उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी पर भरोसा कर सकती है।

xii. डंपिंग और नुकसान का मार्जिन बढ़कर 85-95% हो गया, जबकि लैंडेड कीमत में लगभग 45% की गिरावट आई, जबकि NIP में केवल 18% की गिरावट आई, जिससे पता चलता है कि ड्यूटी बेअसर रही।

xiii. डीआई की पात्रता से जुड़े नियम 2(b) के तहत आपत्ति के लिए कथित संबंधों/आयात की पुष्टि ज़रूरी है; हालाँकि, उपलब्ध सबमिशन में खास तौर पर ऐसी पुष्टि का अनुरोध किया गया है और यह अपने आप में अयोग्यता साबित नहीं करता है।

xiv. ड्यूटी के प्रकार के संबंध में, उत्पाद के रूप, सांद्रता (एकाग्रता) और लेनदेन मूल्य में अंतर को ध्यान में रखते हुए 'एड-वैलोरम' (मूल्यानुसार) ड्यूटी का अनुरोध किया गया था।

xv. यह बताया गया कि डाउनस्ट्रीम यूज़र्स पर एंटी-डंपिंग शुल्क का असर बहुत कम होगा, जिसका अनुमान लगभग ₹35-36 प्रति बोतल लगाया गया है।

च.3 अथॉरिटी द्वारा जांच

51. अथॉरिटी ने देखा है कि एंटी-डंपिंग ड्यूटी लागू होने के बाद, भारत को भेजे जाने वाले संबंधित सामान की एक्सपोर्ट कीमत में लगभग 46% की गिरावट आई, जबकि उसी दौरान मुख्य कच्चे माल की कीमतों में केवल 7.4% की कमी आई। एक्सपोर्ट कीमत में इतनी बड़ी गिरावट को इनपुट लागत में बदलाव से नहीं समझाया जा सकता, और यह गिरावट अमेरिकी डॉलर या भारतीय रुपये, किसी भी मुद्रा में मापे जाने पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसलिए, इसे केवल एक्सचेंज-रेट में उतार-चढ़ाव या वैश्विक कीमतों में बदलाव का नतीजा नहीं माना जा सकता; यह एक्सपोर्ट कीमत में ऐसी कमी को दर्शाता है जो प्रोडक्शन की लागत में हुए किसी भी संबंधित बदलाव के अनुपात में नहीं है।

52. अथॉरिटी इस बात को भी नहीं मान सकती कि एमआईपी से कम कीमत पर होने वाले इंपोर्ट की मात्रा इतनी कम है कि उससे 'एब्जॉर्प्शन' (लागत या शुल्क का अवशोषण) का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। नियम 29 के तहत जांच एक्सपोर्टर के कीमत तय करने के तरीके और ड्यूटी के लगातार असरदार बने रहने पर केंद्रित होती है; न तो नियम 29 और न ही एक्ट की धारा 9A(1B) ऐसे निष्कर्ष के लिए इंपोर्ट की किसी न्यूनतम मात्रा को शर्त के तौर पर तय करती है। अहम बात यह है कि क्या ड्यूटी लगने के बाद भारत को होने वाले एक्सपोर्ट की कीमत में ऐसी गिरावट आई है जिससे ड्यूटी का सुधारात्मक असर कम हो गया हो; जिस मात्रा पर यह गिरावट देखी गई है, उससे यह सवाल तय नहीं होता। इसके अलावा, कीमत तय करने का यह तरीका सिर्फ एमआईपी से कम कीमत वाले कंसाइनमेंट तक ही सीमित

नहीं है। हिस्सा लेने वाले एक्सपोर्टर के कंसाइनमेंट को इंपोर्ट के समय MIP या उसके आस-पास की कीमत पर इसलिए घोषित किया गया था क्योंकि उस कीमत का पालन करना ज़रूरी था; एक्सपोर्टर के अपने वेरिफाइड रिकॉर्ड – ERP डिलीवरी नोट से पुष्टि किए गए ग्रुप ट्रांसफर इनवॉइस – के अनुसार उनकी असल नेट एक्सपोर्ट कीमत 5.85 से 6.25 USD प्रति किलोग्राम के दायरे में थी, यानी यह कीमत उस कंसाइनमेंट के लगभग बराबर थी जो MIP की शर्त के बिना आया था। इस तरह, हिस्सा लेने वाले एक्सपोर्टर के अपने कंसाइनमेंट में भी असल एक्सपोर्ट कीमत में वैसी ही कमी दिखाई देती है, और यह तथ्य कि MIP से कम कीमत वाला कंसाइनमेंट ड्यूटी लगने के बाद कुल इंपोर्ट की गई मात्रा का केवल 10% था, अपने आप में 'एब्जॉर्प्शन' के निष्कर्ष को नहीं रोकता है।

53. USD 5.5-6/kg पर 5 MT का इंपोर्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कीमतें एमआईपी से कम हैं। एमआईपी के आसपास क्लियर किए गए बाकी इंपोर्ट को, बिना सबूत के, स्वतंत्र कमर्शियल प्राइसिंग का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब एक्सपोर्टर ने इसे साबित न किया हो।

54. एमआईपी (न्यूनतम आयात मूल्य) और एंटी-डंपिंग शुल्क अलग-अलग विधानों के अंतर्गत लागू होने वाले पृथक एवं स्वतंत्र उपाय हैं। एमआईपी के अनुरूप घोषित कीमतें नियामकीय अनुपालन को दर्शा सकती हैं और आवश्यक रूप से वास्तविक निर्यात कीमतों को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। अतः प्रासंगिक चीन सीमा शुल्क डेटा तथा सहायक चालानों सहित वास्तविक निर्यात कीमतों पर विचार किया गया है। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि घोषित आयात मूल्य केवल एमआईपी के लागू होने के कारण न्यूनतम आयात मूल्य के आसपास रहे, जबकि वास्तविक निर्यात कीमतें काफी कम थीं। यदि एमआईपी लागू नहीं होता, तो संबंधित वस्तुओं के इन काफी कम मूल्यों पर आयातित होने की पूरी संभावना थी, जिसके परिणामस्वरूप गैर-हानिकारक मूल्य से काफी कम लैंडेड मूल्यों पर आयात में वृद्धि होती। इस प्रकार, वर्तमान में एमआईपी ने सीमा पर वास्तविक निर्यात कीमतों में हुई कमी को छिपाया है; इसने एंटी-डंपिंग शुल्क के अवशोषण को समाप्त नहीं किया है। यह निष्कर्ष इस बात को और पुष्ट करता है कि लागू शुल्क का उपचारात्मक प्रभाव कमजोर हुआ है।

55. जहां मौका मिलने के बावजूद ट्रांज़ैक्शन-वार/तीसरे देश की पूरी जानकारी नहीं दी गई है, वहां अथॉरिटी नियम 6(8) के तहत उपलब्ध सबसे अच्छी जानकारी पर भरोसा कर सकती है।

56. अथॉरिटी ने देखा कि नियम 29 में ड्यूटी के बाद की कोई न्यूनतम अवधि तय नहीं की गई है। एब्जॉर्प्शन के निष्कर्ष का आधार बनने वाले संबंधित ट्रांज़ैक्शन 8 मई 2025 के बाद हुए थे; इसलिए, पहले की अवधि को शामिल करने से जांच अमान्य नहीं हो जाती।

57. नियम 5(3A) (ii) नियम 5 के तहत मूल जांच पर लागू होने वाली POI (जांच की अवधि) की आवश्यकता से संबंधित है और इसे नियम 29 और 30 के तहत की जा रही मौजूदा समीक्षा पर यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।

58. अथॉरिटी ने एक्सपोर्टर-वार जांच और डीजीटीआर की पिछली प्रैक्टिस के बारे में दी गई जानकारी पर विचार किया है। यह फैसला मौजूदा जांच में उपलब्ध सबूतों पर आधारित है, जिसमें रिकॉर्ड पर मौजूद प्राइसिंग की जानकारी भी शामिल है; जहां लागू हो, वहां एक्सपोर्टर-विशिष्ट पूरी जानकारी न होने पर नियम 6(8) के तहत कार्रवाई की जाती है।

59. अथॉरिटी ने डी आई की स्थिति/संभावित संबंधित-पार्टी आयात के संबंध में नियम 2(b) के तहत उठाई गई आपत्ति पर भी विचार किया है। आवेदकों का यूएई में एक संबंधित आयातक है, जो एक गैर-विषय देश है और ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि यूएई में उस इकाई द्वारा खरीदा गया उत्पाद बाद में भारत को निर्यात किया गया हो। इसलिए, अथॉरिटी का मानना है कि नियम 2(b) के संबंध में आवेदक की पात्रता को लेकर कोई लंबित मुद्दा नहीं है।

60. पुनर्मूल्यांकन करने पर, डंपिंग और नुकसान (इंजरी) मार्जिन बढ़कर 85-95% हो गए, जबकि एनआईपी में लगभग 18% की गिरावट के मुकाबले लैंडेड कीमत में लगभग 45% की गिरावट आई; इससे यह साबित होता है कि ड्यूटी के बाद भी लैंडेड कीमत एनआईपी से काफी नीचे बनी रही।

61. इसके अनुसार, अथॉरिटी का मानना है कि निर्यात कीमत में गिरावट, उत्पादन लागत में आई गिरावट के अनुपात में नहीं थी और मौजूदा एंटी-डंपिंग ड्यूटी, नियम 29 के अर्थ में अप्रभावी हो गई है। नतीजतन, नियम 29(2) के तहत ड्यूटी के स्वरूप/मात्रा में उचित बदलाव की जांच की गई है।

छ . निष्कर्ष

62. सभी संबंधित पक्षों की दलीलों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने; और रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों पर विचार करने के बाद, अथॉरिटी इस नतीजे पर पहुंची है:

गैर-गोपनीय

1. मौजूदा एंटी-एब्जॉर्प्शन जांच शुरू करने के लिए आवेदन, नियमों के नियम 30 के अनुसार भारत में समान उत्पाद के उत्पादकों के तौर पर आवेदकों द्वारा दायर किया गया था, और जांच 2 मार्च 2026 की अधिसूचना संख्या 7/02/2026-DGTR के तहत शुरू की गई थी।

2. विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है जो मूल जांच में था, यानी ग्लुफ़ोसिनेट और इसके साल्ट (लवण), तकनीकी और फॉर्मूलेशन दोनों रूपों में; घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबंधित सामान समान उत्पाद हैं; और स्टैंडिंग, नुकसान और कारण संबंध के बारे में मूल जांच के निष्कर्षों को फिर से नहीं खोला जा रहा है।

3. डीजी सिस्टम्स का ट्रांज़ैक्शन-वार डेटा एब्जॉर्प्शन अवधि के दौरान संबंधित सामान के 66 मीट्रिक टन के आयात को रिकॉर्ड करता है, जिसमें से 51 मीट्रिक टन का आयात 8 मई 2025 को एंटी-डंपिंग ड्यूटी लागू होने के बाद किया गया था। ड्यूटी लागू होने के बाद की मात्रा में से, 5 मीट्रिक टन न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) के दायरे से बाहर के टैरिफ आइटम के तहत 5.91 USD प्रति किलोग्राम के सीआईएफ मूल्य पर आए, और बाकी न्यूनतम आयात मूल्य के दायरे में आए।

4. जो खेप न्यूनतम आयात मूल्य की बाध्यता से मुक्त होकर आई, उसकी कीमत आवेदकों द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए चीन कस्टम्स के निर्यात डेटा में दिख रही एफओबी निर्यात कीमतों से काफी हद तक मेल खाती है, और इसे भारत को संबंधित सामान के वास्तविक निर्यात मूल्य के प्रतिनिधि के रूप में अपनाया गया है।

5. इस आधार पर, एब्जॉर्प्शन अवधि के दौरान शुद्ध निर्यात मूल्य 5.561 USD प्रति किलोग्राम है, जबकि मूल जांच में यह 10.259 USD प्रति किलोग्राम तय किया गया था; यानी इसमें लगभग 46% की गिरावट आई है।

6. भाग लेने वाले निर्यातकों ने न तो मार्केट इकोनॉमी ट्रीटमेंट का दावा किया है और न ही मार्केट इकोनॉमी प्रश्नावली भरी है, और इसलिए उनका लागत डेटा सत्यापन योग्य रूप में उपलब्ध नहीं है; उत्पादन लागत में बदलाव की जांच मुख्य कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के आधार पर एक सरोगेट (विकल्प) के रूप में की गई है, जिसमें लगभग 7.4% की गिरावट दिखाई देती है।

7. इसलिए, भारत को होने वाले निर्यात की कीमत में आई कमी, उत्पादन लागत में हुए बदलाव के अनुपात में नहीं है, और नियम 29(1) के पहले हिस्से के तहत 'एब्जॉर्प्शन' (लागत या शुल्क का अवशोषण) की शर्त पूरी होती है।

8. भाग लेने वाले निर्यातकों ने किसी भी ट्रांज़ैक्शन के लिए तीसरे देश को किए गए निर्यात का डेटा रिकॉर्ड पर नहीं रखा है, और रिकॉर्ड पर मौजूद रीसेल-प्राइस (पुनर्विक्रय मूल्य) का डेटा स्वतंत्र रूप से 'एब्जॉर्प्शन' का संकेत नहीं देता है; नियम 29(1) के अलग-अलग हिस्सों को देखते हुए, यह निष्कर्ष पहले हिस्से पर आधारित है।

9. नियम 29(2) के तहत दोबारा मूल्यांकन करने पर, 'एब्जॉर्प्शन' की अवधि के लिए 'कंस्ट्रक्टेड नॉर्मल वैल्यू' (तय की गई सामान्य कीमत) 10.565 USD प्रति किलोग्राम और 'नॉन-इंजुरियस प्राइस' (बिना नुकसान वाली कीमत) 12.415 USD प्रति किलोग्राम है।

10. डंपिंग मार्जिन मूल अवधि में 20-30% की रेंज से बढ़कर 'एब्जॉर्प्शन' अवधि में 85-95% की रेंज में पहुंच गया है, और इंजरी मार्जिन (नुकसान का मार्जिन) भी 20-30% की रेंज से बढ़कर 85-95% की रेंज में पहुंच गया है। मूल अवधि के लिए तय किया गया डंपिंग मार्जिन, जो 2.998 USD प्रति किलोग्राम था, वर्तमान में लागू एंटी-डंपिंग ड्यूटी के अनुरूप है। प्रति-यूनिट के हिसाब से, दोबारा तय किया गया डंपिंग मार्जिन (जो *** है) दोनों मार्जिन में से कम वाला है।

11. वर्तमान में लागू एंटी-डंपिंग ड्यूटी को ध्यान में रखने के बाद भी, संबंधित आयात की 'लैंडेड प्राइस' (आयातित माल की भारत में पहुंचने पर कीमत) 'नॉन-इंजुरियस प्राइस' से काफी कम बनी हुई है।

12. इसके अनुसार, वर्तमान में लागू एंटी-डंपिंग ड्यूटी को निर्यातकों द्वारा 'एब्जॉर्ब' (अवशोषित) कर लिया गया है और यह एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 29 के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम की धारा 9A(1B) के अर्थ में अप्रभावी हो गई है।

13. एंटी-डंपिंग ड्यूटी की बदली हुई मात्रा केवल भविष्य के लिए लागू होगी, न कि पिछली तारीख से (बिना रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव के); जबकि ड्यूटी का मौजूदा स्वरूप वैसा ही रहेगा और केवल उसकी मात्रा में बदलाव किया जाएगा।

झ. सिफ़ारिश

63. अथॉरिटी ने देखा कि जांच शुरू की गई और सभी संबंधित पक्षों को इसकी सूचना दी गई। साथ ही, घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य संबंधित पक्षों को 'एब्ज़ॉर्प्शन' (लागत या शुल्क का बोझ खुद उठाना) के पहलू पर सकारात्मक जानकारी देने का पूरा मौका दिया गया। एंटी-डंपिंग नियमों के तहत चीनी उत्पादकों पर शुल्क के एब्ज़ॉर्प्शन की जांच शुरू करने और उसे पूरा करने के बाद, अथॉरिटी का मानना है कि चीनी उत्पादकों पर लागू एंटी-डंपिंग शुल्क में बदलाव की ज़रूरत है। इसलिए, अथॉरिटी संबंधित देश से संबंधित सामान के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क की मात्रा में बदलाव की सिफ़ारिश करती है।

64. अथॉरिटी, चीन (PR) से आने वाले या वहां से निर्यात किए जाने वाले संबंधित सामान पर लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क की मात्रा में बदलाव की सिफ़ारिश करती है। यह बदलाव 'फ़ाइनल फ़ाइंडिंग नोटिफ़िकेशन' नंबर F. No. 6/19/2024- डीजीटीआर (10 फ़रवरी 2025) और नोटिफ़िकेशन नंबर 09/2025-कस्टम्स (एंटी-डंपिंग शुल्क) (8 मई 2025) के तहत नीचे दिए गए तरीके से किया जाएगा। मामले के तथ्यों, दी गई जानकारी और संबंधित पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क की मात्रा में बदलाव करना उचित समझा गया है। एंटी-डंपिंग शुल्क की बदली हुई मात्रा केवल भविष्य के लिए लागू होगी और इसे पिछली तारीख से लागू नहीं किया जाएगा; साथ ही, एंटी-डंपिंग शुल्क का मौजूदा रूप/प्रकार वही रहेगा, केवल उसकी मात्रा में बदलाव किया जाएगा।

65. अथॉरिटी ने घरेलू इंडस्ट्री की उस रिक्वेस्ट पर विचार किया है जिसमें नियम 31 के तहत जांच शुरू होने की तारीख से बदले हुए ड्यूटी को पिछली तारीख से लागू करने और जांच शुरू होने के समय नियम 30(5) के तहत प्रोविज़नल असेसमेंट की सिफारिश की गई थी। नियम 31 पिछली तारीख से लागू करने की इजाज़त देता है, लेकिन इसके लिए मजबूर नहीं करता; यह मामला अथॉरिटी के विवेक पर निर्भर करता है, जिसमें रिव्यू के सुधारात्मक मकसद और 'कम-ड्यूटी' के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है। यह मकसद सुधारात्मक है, दंडात्मक नहीं, और ड्यूटी में भविष्य के लिए बदलाव करके इसे पूरी तरह से हासिल किया जा सकता है। रिव्यू के दौरान, संबंधित सामान भारत में घोषित मूल्यों पर आया, जो न्यूनतम आयात मूल्य के बराबर या उसके आसपास थे - यानी, गैर-हानिकारक मूल्य के बराबर या उससे अधिक - और उन पर उस समय लागू ड्यूटी लगाई गई थी; भारत में उनकी रीसेल कीमत में कोई गिरावट नहीं देखी गई; इसलिए, पिछली तारीख से ड्यूटी लगाकर रोकने के लिए हानिकारक लैंडेड मूल्यों पर आयात की कोई बाढ़ नहीं आई थी। यह 'एब्जॉर्प्शन' (लागत या ड्यूटी का बोझ खुद उठा लेने) के निष्कर्ष से अलग है, जो एक्सपोर्टर्स के

वास्तविक एक्सपोर्ट-प्राइसिंग व्यवहार पर आधारित होता है और भविष्य के लिए ड्यूटी को फिर से तय करने की मांग करता है। 'कम-ड्यूटी' सिद्धांत को लागू करते हुए, अथॉरिटी भविष्य के लिए इसे लागू करना पर्याप्त मानती है और पिछली तारीख से लागू करने की सिफारिश नहीं करती है; इसलिए, नियम 30(5) के तहत प्रोविज़नल असेसमेंट वाले आयात का अंतिम असेसमेंट संबंधित अवधि के दौरान लागू ड्यूटी की दर पर किया जाएगा।

66. 'लेसर ड्यूटी रूल' (कम शुल्क का नियम) को ध्यान में रखते हुए, अथॉरिटी घरेलू इंडस्ट्री को हुए नुकसान को दूर करने के लिए डंपिंग मार्जिन और इंजरी मार्जिन (नुकसान के मार्जिन) में से जो भी कम हो, उसके बराबर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश करती है। इसके अनुसार, अथॉरिटी संबंधित देश से आने वाले या वहां से एक्सपोर्ट किए जाने वाले संबंधित सामान पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी की मात्रा में बदलाव करके उसे नीचे दी गई ड्यूटी टेबल के कॉलम 7 में बताई गई राशि के बराबर करने की सिफारिश करती है। बदली हुई ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन की तारीख से लागू होगी और 8 मई 2025 के नोटिफिकेशन नंबर 09/2025-कस्टम्स (एंटी-डंपिंग ड्यूटी) के तहत लगाई गई एंटी-डंपिंग ड्यूटी की बची हुई अवधि के लिए लागू रहेगी।

ड्यूटी टेबल

क्रम संख्या	हेडिंग/सब-हेडिंग*	सामान का विवरण	उत्पत्ति का देश	निर्यात करने वाला देश	उत्पादक	मात्रा	माप की इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	38089193, 38089199, 38089391, 38089399, 38089912,	ग्लूफ़ोसिनेट और उसका सॉल्ट	चीन पी आर	चीन पीआर (PR) सहित	अन्य	5004	एम टी	यू एस डी

	38089991 and 38089999			कोई भी अन्य देश				
2	-do-	-do-	चीन पीआर (PR) सहित कोई भी अन्य देश	चीन पी आर	अन्य	5004	एम टी	यू एस डी

*कस्टम्स वर्गीकरण केवल संकेत देने वाला है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ञ. **आगे की प्रक्रिया**

67. अंतिम निष्कर्षों के आधार पर अथॉरिटी के आदेश के खिलाफ़ अपील, एक्ट के संबंधित प्रावधानों के अनुसार कस्टम्स, एक्साइज़ और सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष की जा सकती है।

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 01-09-2026
17:46:55